घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 64- शनिवार 03- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को वायु प्रदूषण से मिली राहत,एक्यूआई 236 दर्ज

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को लंबे समय बाद प्रदूषण की मात्रा कम होने से यहां के लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 236 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 236 दर्ज किया गया है जबकि नोएडा का 229,ग्रेटर नोएडा 238 और गुरुग्राम का एक्यूआई 187 दर्ज किया गया है, जो 'खराब' तथा 'मध्यम' श्रेणी को दर्शाते हैं। आज राजधानी के अधिकतर इलाकों का एक्यूआई 300 से कम दर्ज किया गया है। इनमें नजफगढ़ का 291,अशोक विहार का 284, पंजाबी बाग का 279,सोनिया विहार का 274, आईआईटी का 268, आईटीओ का 261,अलीपुर का 260,नरेला का 255,मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का 254,श्री अरबिंदों मार्ग का 251, मंदिर मार्ग का 228,बुराड़ी का 224,लोधी रोड आईएमडी का 222 पाया गया है, जबकि अया नगर का एक्यूआई 196 रहा। इसके अलावा आनंद विहार का एक्यूआई 318,जहांगीरपुरी का 305, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का 305, सिरीफोर्ट का 317 और चांदनी चौक का 312 दर्ज किया गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे और सुबह के समय कहीं-कहीं पर हल्का कोहरा तथा कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रहा। यहां का अधिकतम तापमान 16-18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9-11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। छह जनवरी तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में शीत लहर के आसार हैं।

एनएचएआई : 1 फरवरी 2026 के बाद जारी होने वाले नए फास्टैग वाली कारों के लिए केवाईवी बंद

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 फरवरी 2026 से सभी नए जारी किए गए फास्टैग वाली कारों (कार/जीप/वैन श्रेणी फास्टैग) के लिए 'नो योर व्हीकल (केवाईवी)' की प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है। सक्रिय किए जाने से पहले सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी जारीकर्ता बैंकों को सौंपकर, एनएचएआई का लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले लोगों को परेशानी से मुक्त अनुभव प्रदान करना है। यह सुधार सड़क का उपयोग करने वाले उन लाखों आम लोगों को बड़ी राहत देगा, जिन्हें वाहनों के मान्य दस्तावेज होने के बावजूद फास्टैग के सक्रिय होने के बाद जारी होने के उपरांत केवाईवी संबंधी जरूरतों के कारण असुविधा और देरी का सामना करना पड़ रहा था। कारों के लिए पहले से जारी मौजूदा फास्टैग के लिए, अब केवाईवी रूटीन जरूरत के तौर पर अनिवार्य नहीं होगा। केवाईवी केवल वैसे खास मामलों में जरूरी होगा जहां ढीले फास्टैग, गलत जारी होने, या गलत इस्तेमाल से जुड़ी समस्याएं जैसी शिकायतें मिलती हैं। किसी भी शिकायत के न होने पर, मौजूदा कार फास्टैग के लिए किसी केवाईवी की जरूरत नहीं होगी। फास्टैग को सक्रिय करने की अनुमति केवल वाहन डेटाबेस से वाहन के विवरण के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी। सक्रिय होने के बाद सत्यापन की अनुमति देने वाला पहले का प्रावधान बंद कर दिया गया है।

इंदौर दूषित पानी मामले में अब तक 15 लोगों की मौत

सरकार ने हाई कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट,बताया...केवल चार मौते हुईं

इंदौर,02 जनवरी 2026। इंदौर में गंदे पानी से मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश कर दी, इसमें पानी से सिर्फ 4 मौत होने की बात कही है। सरकार की रिपोर्ट की ये स्थिति तब है, जब 15 मौतों की जानकारी सामने आ चुकी है। इनमें 5 महीने के मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में भी पानी में सीवेज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,सांसद शंकर लालवानी और सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी खुद पाइपलाइन लीकेज व पानी में सीवेज मिला होने की बात कह चुके हैं। मंत्री विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र के भागीरथपुरा के 16 बच्चों समेत 201 लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 6 जनवरी तय की है। वहीं, इंटर विनर (हस्तक्षेप कर्ता) गोविंद सिंह बैस की ओर से मीडिया में रिपोर्ट पब्लिश करने पर रोक लगाने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध इंदौर के साथ ही भोपाल,जबलपुर, रतलाम और नर्मदापुरम में भी हो रहा है। वहीं,पूर्व सीएम उमा भारती ने इसे सीएम मोहन यादव के लिए परीक्षा की घड़ी बताया। इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि साफ पानी अहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है।

राहुल बोले...जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा...

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा...इंदौर में पानी नहीं,जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर-घर मातम है,गरीब बेबस हैं और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है,उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की- फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये 'फोकट' सवाल नहीं...ये जवाबदेही की मांग है।

जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये नहीं होती : उमा भारती

इंदौर में दूषित पानी से मौतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स लिखा है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड! उन्होंने लिखा है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश,हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है,मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है।

सरकार ने 4 मृतकों के नाम बताए...

राज्य सरकार ने 39 पेज की स्टेट्स रिपोर्ट में बताया कि दूषित पानी से चार सीनियर सिटीजन की मौत हुई है। सभी की उम्र 60 साल से ज्यादा है। इनमें उर्मिला की मौत 28 दिसंबर, तारा (60) और नंदा (70) की 30 दिसंबर और हीरालाल (65) की 31 दिसंबर को हुई।

पूर्व गृह मंत्री ने कहा- दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए...

पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता हिम्मत कोठारी ने कहा... इस मामले में जांच केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे। दोषियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

भारत का युवा जाग गया है,वह अपने देश को समर्थ बनाना चाहता है : भागवत

भोपाल,02 जनवरी 2026। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने कहा कि भारत का युवा जाग गया है, वह अपने देश को समर्थ बनाना चाहता है। संघ अपने जन्म से ही लक्ष्य लेकर चल रहा है कि अपने धर्म-संस्कृति का संरक्षण कर,अपने भारत को परम वैभव पर लेकर जाना है। संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक यह प्रतिज्ञा करता है। सरसंघचालक डा. भागवत ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के प्रवास के तहत यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में युवाओं से संवाद में कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी देश सम्पूर्ण समाज के योगदान से ही बड़ा होता है। नेता,नीति और व्यवस्था,ये सब तब सहायक होते हैं,जब समाज गुणसम्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि अब भारत का युवा जाग गया है, वह अपने देश को समर्थ बनाना चाहता है। दरअसल,संघ प्रमुख भोपाल में शुक्रवार और शनिवार को दो दिवसीय प्रवास हैं। उन्होंने आज

पहले दिन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में युवाओं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित इस 'युवा संवाद' कार्यक्रम में संवाद किया। इसमें मध्यभारत प्रान्त के 16 शासकीय जिलों के युवाओं को सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के साथ सीधे संवाद करने और उनसे प्रश्न करने का अवसर मिला। इसमें उन्होंने कहा कि संघ युवाओं से आह्वान करता है कि वे संघ की शाखा में आएं या फिर संघ की योजना से चल रहे अपने रुचि के कार्य में जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। सरसंघचालक ने कहा, 'यदि हमें देश के लिए कुछ करना है तो इस मार्ग में हमें गुणों को धारण करना होगा और अहंकार व स्वार्थ छोड़ने होंगे। दुनिया में संघ ने ही एकमात्र ऐसी पद्धति दी है,जो अच्छी आदतें विकसित करती है। संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवारजी हर क्षेत्र में कार्य करते थे। लेकिन उन्हें चिंता यह थी कि देश में एकता कैसे स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि इस भाव को उत्पन्न करने वाले संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और दुनिया में कहीं दूसरी पद्धति नहीं है व्यक्ति निर्माण की।' उन्होंने कहा कि संघ की शाखा देशभक्ति सिखाती है। यदि इसका अनुभव लेना है और उद्देश्य को जीना है तो शाखा एकमात्र जगह है। जहां कोई बंधन नहीं है। सरसंघचालक ने इस दौरान यह भी कहा कि'हम कई बार असुरक्षा और चिंता के साथ जीते हैं, लेकिन इसकी बजाय हमें भयमुक्त होकर जीना चाहिए।

विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं,छात्रों को हर दिन ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

चेन्नई,02 जनवरी 2026। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के वानगर स्थित डॉ. एम.जी.आर. शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 34वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 5,500 से अधिक छात्रों को विभिन्न विषयों में डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें सामान्य चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 20 से अधिक मेधावी छात्रों को उपराष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से डिग्रियां और सम्मान प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नया साल आपसी सौहार्द और शुभेच्छाओं के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चेन्नई जैसे महानगर में नए साल के बाद यह उनका पहला कार्यक्रम है और यह शहर हमेशा बदलावों को खुले मन से अपनाने के लिए जाना जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह इसकी निरंतर प्रगति का प्रतीक है। यह संस्थान वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां से वे नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। सभी स्नातकों से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहें, ताकि वे न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकें।

श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तानी ड्रोन ड्रग्स गिराते समय क्रैश, 4.88 किलो हेरोइन बरामद

ड्रोन के माध्यम से करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन भेजी,तीन गिरफ्तार

श्रीगंगानगर,02जनवरी 2026। पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए ड्रोन से की जा रही नशे की तस्करी का एक बड़ा मामला श्रीगंगानगर जिले में सामने आया है। नए साल की रात एक जनवरी को पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन भारत भेजी, लेकिन ड्रग्स गिराते समय ड्रोन क्रैश हो गया। रावला थाना पुलिस ने मौके से 4.88 किलो हेरोइन, एक ड्रोन सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहान ने शुक्रवार को

घड़साना पुलिस थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि हेरोइन की खेप सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। जिस स्थान पर हेरोइन गिराई गई, वहीं ड्रोन भी तकनीकी कारणों से क्रैश हो गया। रावला थाना पुलिस एक जनवरी की रात गश्त पर थी।

दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे...हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार : जयशंकर

चेन्नई,02 जनवरी 2026। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर शुक्रवार को तमिलनाडु की आईआईटी मद्रास पहुंचे। यहां विदेश मंत्री ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से, हमारे हैं। अगर कोई देश यह तय करता है कि वह जानबूझकर, लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम उस अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यह हम पर निर्भर है। कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। हम खुद को बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, वह करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि कई साल पहले हमने पानी बांटने की व्यवस्था पर सहमति जताई थी, लेकिन अगर दशकों तक आतंकवाद होता है तो अच्छे पड़ोसी होने की भावना नहीं रहती। जयशंकर ने आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम शास्त्र 2026 का उद्घाटन भी किया। इस दौरान विदेशों में आईआईटी मद्रास की शाखाएं खोलने को लेकर कई एमओयू भी साइन हुए।

बांग्लादेश पर कहा...अच्छे लोग नुकसानदायक नहीं

बांग्लादेश में अशांति पर विदेश मंत्री ने कहा...'मैं अभी दो दिन पहले बांग्लादेश में था। मैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने गया था। हमें कई तरह के पड़ोसी मिले हैं। अगर आपका कोई पड़ोसी आपके लिए अच्छा है या कम से कम आपके लिए नुकसानदायक नहीं है तो इसमें परेशानी नहीं है। जहां भी अच्छे पड़ोसी होने की भावना होती है, भारत निवेश करता है, भारत मदद करता है,भारत शेयर करता है।'

विदेश मंत्री की स्पीच की मुख्य बातें...

- भारत दुनिया की उन पुरानी सभ्यताओं में से है, जो आज एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में मौजूद हैं। भारत को अपने इतिहास और विरासत का स्पष्ट एहसास है, जो बहुत कम देशों में देखने को मिलता है।
- भारत ने जानबूझकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, जिससे लोकतंत्र एक वैश्विक राजनीतिक विचार बना। भारत की जिम्मेदारी है कि वह अपने विचार, संस्कृति और इतिहास को दुनिया के सामने रखे।
- पश्चिमी देशों के साथ साझेदारी जरूरी है और यह साझेदारी सकारात्मक तरीके से की जा सकती है। 'वसुधैव कुटुंबकम' का अर्थ है कि भारत ने दुनिया को कभी दुश्मन या खतरे के रूप में नहीं देखा।
- सीमित संसाधनों के बावजूद ज्यादा प्रभाव कैसे डाला जाए, यही भारत की विदेश नीति की सोच है। भारतीय कूटनीति अपनी ताकत, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक संस्थानों का उपयोग करके समाधान तलाशती है।
- छोटे और गरीब देशों के लिए भारत की वैक्सीन मदद 'जीवनरेखा' जैसी थी। भारत दुनिया के सबसे कुशल वैक्सीन उत्पादकों में से एक है। वैश्विक सप्लाई चेन भारत के बाहर से आती है, इसलिए दुनिया के साथ सहयोग जरूरी है।

विदेश मंत्री बोले...अरुणाचल भारत का हिस्सा है और रहेगा

विदेश मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, और इस तरह की चालों से जमीन पर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों के अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के परेशान करने को लेकर जयशंकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हमने असल में इसका विरोध किया, और हमने यह बात भी साफ कर दी कि इस तरह की हरकतें करने से असल में कुछ भी बदलने वाला नहीं है।

कर्नाटक सरकार के सर्वे में दावा-91% ने माना चुनाव निष्पक्ष

राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे,भाजपा बोली...नागरिकों को विश्वास,कांग्रेस को शक

बेंगलुरु,02 जनवरी 2026। कर्नाटक सरकार की एक एजेंसी की स्टडी में दावा किया गया है कि राज्य के 91% लोग मानते हैं कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं और ईवीएम सटीक नतीजे देती हैं। यह रिपोर्ट कर्नाटक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी ने प्रकाशित की है। यह सर्वे ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भाजपा पर कई राज्यों में 'वोट चोरी' का लगातार आरोप लगा रहे

हैं। वे कर्नाटक के कलबुर्गी में भी वोट चोरी का दावा कर चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में भाजपा ने सर्वे रिपोर्ट को लेकर राहुल पर पलटवार किया है। भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'लोग चुनावों पर, ईवीएम पर और लोग भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। यह सर्वे कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। जहां नागरिक भरोसा दिखा रहे हैं, वहीं कांग्रेस शक जता रही है।' सूत्रों के अनुसार, चुनाव को लेकर रिपोर्ट अगस्त 2025 में तैयार हुई थी, जो हाल में सार्वजनिक की गई है।

हताश निराश ममता अब गृह मंत्री को धमकी दे रही हैं : भाजपा

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई धमकी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा ने कहा कि गृह मंत्री और नागरिकों को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की मूल भावना, अनुच्छेद 19 कहता है कि हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है। भारत की एक-एक इंच भूमि पर हर भारतीय का हक है। भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के भाई-बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री,जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे,वही भारत के गृहमंत्री को धमकी देती हैं कि मैं न चाहूं तो भारत के गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते। जंगलराज,गुंडाराज ऐसा ही होता है। जहाँ ममता बनर्जी को लगता है कि रोहिंग्या उनका वोट बैंक हैं, उनके साथ ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, और गृहमंत्री को धमकी देती हैं। ममता बनर्जी ने यह हक खो दिया है कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहें। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता कहते है कि बंगाल में तृणमूल सिर्फ वोट नहीं चुराती बल्कि वोटों की डकैती करती है।

संपादकीय

कमजोर कड़ियों से मुक्ति आवश्यक

पीएम मोदी को कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे...

गोवा का नाइट क्लब भी शासन-प्रशासन के स्तर पर घोर लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण रहा...क्लब में लगी आग में 25 लोग मारे गए और कई घायल हुए...कई आवश्यक स्वीकृतियों के बिना भी इस क्लब का संचालन हो रहा था... इसका प्रवेश और निकास मार्ग ही इतना संकरा था कि राहत एवं बचाव अभियान में तमाम बाधाएं आईं...

नए साल में कुछ नई चुनौतियां भी साथ आई हैं। देश और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी को इन चुनौतियों का सामना करना है। स्वाभाविक रूप से ऐसी चुनौतियों के कुछ तार कहीं न कहीं पिछले साल से भी जुड़े हुए हैं। अस्थिरता के शिकार वैश्विक ढांचे में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने जो अनिश्चितता बढ़ाई, उससे उपजी चुनौतियों को प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता से संभाला। हालांकि इंडिगो संकट,अरावली खनन,प्रदूषण से कराहती राष्ट्रीय राजधानी के मुद्दे बेहद परेशान करने वाले रहे। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक को मिली राहत जैसी घटना भी चौंकाने वाली रही। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना में जिंदा जले लोग भी राज्य सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार के शिकार बने। यह भी एक दुर्योग रहा कि ऐसे सभी मामले साल की अंतिम तिमाही के दौरान सामने आए, जो कहां न कहीं दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के पास न केवल केंद्रीय, बल्कि राज्यों के स्तर पर भी सक्षम मंत्रियों एवं नौकरशाहों का अभाव है,जो एक पारदर्शी एवं प्रभावी सरकार की योजनाओं को लागू करने में सहायक बन सकें।

इंडिगो प्रकरण की ही बात करें तो विमानन नियामक ने इस कंपनी को ऐसी गुंजाइश ही क्यों दी कि वह बाजार के 65 प्रतिशत हिस्से पर काबिज हो सके। उसे परिचालन विस्तार के लिए ऐसी अनुमति कैसे मिलती गई कि वह नियामक को ही अपनी अंगुलियों पर नचा सके? ऐसे में डीजीसीए के ढांचे और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्या उसके अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं या महज उसमें नियुक्ति पाने वाले नौकरशाह ही हैं। दिसंबर की शुरुआत में विमान सेवाओं के एक बड़े हिस्से के करीब-करीब ठप पड़ने के कई सप्ताह बाद भी इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं।

जहां तक अरावली मुद्दे का सवाल है तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में नवंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव किया। हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने उस फैसले पर स्थगन का निर्णय किया। नवंबर में अदालत ने सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल द्वारा दी गई एक अजीब परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। इसमें अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था। जहां मंत्रालय ने अपनी तथाकथित विशेषज्ञ समिति की इस राय का जोरदार बचाव किया,वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने नवीनतम आदेश में इसके विपरीत रुख अपनाया। सरकार की 'विशेषज्ञ समिति' की बात करें तो उसमें अधिकांश सदस्य पर्यावरण विशेषज्ञ न होकर नौकरशाह ही थे। इस मामले को लेकर रुख बदलने में मीडिया के सवालों की अहम भूमिका रही है। मीडिया के माध्यम से ही यह हैरान करने वाली जानकारी भी सामने आई कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सरकार ने दर्जनों खनन पट्टों को त्वरित गति से स्वीकृति प्रदान की। यदि यह सच है तो एक बड़ी विडंबना को ही दर्शाता है कि खनन माफिया पूरे परिदृश्य को किस हद तक प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार इस मामले में समय से स्पष्टता नहीं दिखा सकी, जिससे उसकी छवि प्रभावित हुई।

यह किसी से छिपा नहीं रह गया है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण के मामले में नए कीर्तिमान बनाती जा रही है,लेकिन पर्यावरण मंत्रालय के पास इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिहाज से कुछ उल्लेखनीय नहीं है। बीते साल कुछ दिनों के दौरान एक्यूआइ का आंकड़ा 500 से 1,000 तक पहुंचता दिखा,लेकिन पर्यावरण मंत्रालय ने किसी निदान के बजाय दोषारोपण का सहारा लेने को ही प्राथमिकता दी। कभी पराली को लेकर अंगुली उठाई गई तो कभी आम आदमी पार्टी पर। प्रदूषण से निपटने में किसी कारगर कार्ययोजना के मामले में दिल्ली सरकार भी अकर्मण्य ही नजर आई। इसका ही परिणाम है कि दिल्ली रहने के लिहाज से बेहद खतरनाक शहर बन गया है। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है।

गुजरे हुए साल के अंतिम दिनों में उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत भी चर्चा के केंद्र में रही। सीबीआइ की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट भी दिया। कुछ वर्ष पूर्व यह मामला सामने आने के बाद सेंगर को भाजपा ने निष्कासित कर दिया था,लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे व्यक्ति को पहले-पहल भाजपा में शामिल ही क्यों किया गया? इस पूरे मामले में कई कानूनी सवाल भी उठते हैं,क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर जेल में बंद है। सेंगर पर सख्ती के मामले में भी मीडिया के रुख की अहम भूमिका रही।

गोवा का नाइट क्लब भी शासन-प्रशासन के स्तर पर घोर लापरवाही का ज्वलंत उदाहरण रहा। क्लब में लगी आग में 25 लोग मारे गए और कई घायल हुए। कई आवश्यक स्वीकृतियों के बिना भी इस क्लब का संचालन हो रहा था। इसका प्रवेश और निकास मार्ग ही इतना संकरा था कि राहत एवं बचाव अभियान में तमाम बाधाएं आईं। क्या यह सब पहले नहीं दिख रहा था? ऐसे में, सवाल उठना स्वाभाविक है कि किसकी कृपा से क्लब को लाइसेंस मिला और वहां जिम्मेदार लोगों ने सुरक्षा प्रबंधों की सुध लेने की जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी। इस परिदृश्य को देखते हुए यह कहना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने का समय आ गया है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की संरचना से लेकर उन लोगों के संबंध में कुछ कड़े निर्णय करने होंगे,जो भाजपा शासित राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अन्यथा अप्रिय घटनाएं उनकी छवि पर नकारात्मक असर डालेंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उन्हें अविलंब कड़ा रुख अपनाना होगा।

कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध के खतरे

डॉ विजय गर्ग
मलोट पंजाब

मानव सभ्यता के विकास की कहानी में आग के आविष्कार के बाद, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे क्रांतिकारी माना गया। इसने मनुष्य को अंधेरे पर विजय दिलाई और रात को दिन में बदल कर हमारी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। हमने शहरों को जगमग कर दिया,घरों को रोशन किया और अपनी रातों को भी दिन की तरह सक्रिय बना लिया। हम इसे विकास और आधुनिकता का नाम देते हैं, लेकिन आज यही विजय हमारी सबसे बड़ी जैविक पराजय का कारण बनती जा रही है। जिस कृत्रिम रोशनी को हमने अपनी सुविधा के लिए ईजाद किया था,वह अब एक ऐसे अदृश्य खतरे में तब्दील हो चुकी है, जो हमारे शरीर के सबसे महत्त्वपूर्ण अंगों खासकर हमारे दिल को अपना शिकार बना रही है।

हालिया वैज्ञानिक अध्ययन हमें जिस गंभीर खतरे से आगाह कर रहे हैं, न केवल चौंकाने वाला है,बल्कि हमारी पूरी आधुनिक जीवनशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता रात का यह अनावश्यक प्रकाश हमारे दिल की सेहत के लिए एक धीमा जहर बन गया है। हममें से अधिकांश लोग इस एक खतरे से पूरी तरह अनजान हैं। हम रोशनी को सुरक्षा और सकारात्मकता से जोड़ते हैं,जबकि जबकि अंधेरे को डर से,लेकिन जीव विज्ञान की दृष्टि से हकीकत इसके ठीक विपरीत । हाल ही में हुए व्यापक और गहन शोधों इस बात की पुष्टि की है कि रात के समय कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहना केवल हमारी नींद खराब नहीं करता,बल्कि यह हृदय संबंधी जानलेवा बीमारियों का सीधा और प्रमुख कारण बन रहा है। ये अध्ययन उन करोड़ों लोगों के लिए एक चेतावनी है,जो मानते हैं कि रात में थोड़ी सी रोशनी,टीवी या फोन का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है।

आंकड़ों की बात करें तो स्थिति बेहद भयावह नजर आती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग रात में अधिक तेज या लगातार कृत्रिम रोशनी के संपर्क में रहते हैं, उनमें दिल काम न करने का खतरा 56 फीसद तक बढ़ जाता है। चिकित्सा विज्ञान इसे खतरनाक माना गया है। इसी तरह,दिल के दौरे का खतरा 47 फीसद तक और स्ट्रोक या अन्य जानलेवा स्थितियों का जोखिम तीस फीसद से अधिक पाया गया है। ये केवल कागजी संख्या नहीं हैं, बल्कि यह उन लाखों जिंदगियों का संकेत हैं,जो अपनी अज्ञानता के कारण समय से पहले काल गाल में समा सकती हैं। इस शोध का सबसे अधिक चिंताजनक पहलू सामने आता है कि यह जोखिम उन लोगों में भी समान रूप से देखा गया,जो अपनी सेहत और शारीरिक गतिविधियों को लेकर बेहद सतर्क थे।

हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अच्छा और संतुलित भोजन कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं, धूम्रपान नहीं करते और शराब से दूर रहते हैं,तो हमारा दिल पूरी तरह सुरक्षित है। मगर यह नया अध्ययन हमारी इस गलतफहमी को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कृत्रिम रोशनी का दुष्प्रभाव उन लोगों पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया, जिनकी जीवनशैली आदर्श थी। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि रात का प्रकाश भी एक बड़ा जोखिम है। आप दिन भर कितना भी दौड़ लें या कितना भी पौष्टिक आहार ले लें, यदि आप रात के समय अंधेरे में नहीं सोते हैं, तो आपका दिल खतरे में है। यह तथ्य स्वास्थ्य जगत में एक नए प्रतिमान को स्थापित करता है,जहां अंधेरा अब विटामिन और व्यायाम की तरह ही अच्छे स्वास्थ्य का एक अनिवार्य स्तंभ बन गया है। इस खतरे को समझने के लिए हमें मानव शरीर के विकासवादी इतिहास और उसकी जैविक संरचना को समझना होगा।

लाख वर्षों से मानव शरीर पृथ्वी के घूमने और सूर्य के उगने ढलने के प्राकृतिक चक्र के साथ तालमेल बना कर विकसित हुआ है। हमारे पूर्वज दिन के उजाले में शिकार के अलावा अन्य काम करते थे और रात के अंधेरे में विश्राम करते थे। लाखों वर्षों की इस प्रक्रिया ने हमारे डीएनए में एक 'जैविक घड़ी को स्थापित कर दिया है। यह घड़ी प्रकाश और अंधकार के संकेतों पर चलती अंधेरा छाता है, हमारी आंखो जस ही सूरज ढलता है और 7 के रेटिना के माध्यम से दिमाग को संदेश मिलता है कि अब काम बंद करने और आराम करने का समय है। इस संदेश के मिलते ही हमारा मस्तिष्क पीनियल ग्रंथि के जरिए मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देता है। मेलाटोनिन नामक एक बहुत को आम भाषा में अक्सर केवल नींद का हार्मोन समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह उससे 7 कहीं अधिक अहम होता है।

जब रात में मेलाटोनिन का स्राव होता है, तो यह हमारे शरीर के तापमान को थोड़ा कम करता है,हमारे रक्तचाप को घटाता है और दिल की धड़कन को धीमा एवं स्थिर करता है। यह वह समय होता है, जब हमारा दिल जो दिन भर बिना रुके हजारों लीटर खून पंप करता है और हमारा मानसिक एवं शारीरिक तनाव झेलता है,वह थोड़ा सुस्ताता है और अपनी मरम्मत करता है। दिन की भाग-दौड़, चिंता और प्रदूषण से हमारी रक्त वाहिकाओं तथा हृदय की मांसपेशियों में जो सूक्ष्म टूट-फूट होती है,उसे ठीक करने का काम इसी अंधेरे के दौरान मेलाटोनिन की देखरेख में संभव हो पाता है। यह एक प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली है,जो हमारे शरीर को अगले दिन के लिए तरोताजा करती है। शहरीकरण इस समस्या को और विकराल बना दिया है। हम ऐसे शहरों में रहते हैं, जो कभी नहीं सोते और जगमगाते रहते हैं। इसे प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। पहले प्रदूषण का मतलब केवल हवा या पानी का गंदा होना था, लेकिन अब प्रकाश ने भी प्रदूषण का रूप ले लिया है,जो हमारे स्वास्थ्य को प्रतिदिन नष्ट कर रहा है। वैज्ञानिक अब इस बात पर हैं कि रात का प्रकाश मधुमेह और मोटापे जैसी चयापचय संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है, जो आगे चल कर हृदय रोगों का कारण बनते हैं। मगर इस गंभीर खतरे को टालना पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। सबसे पहले हम अपने शयनकक्ष में अंधेरे को तवज्जो दें। सुनिश्चित करें कि कमरे में किसी भी स्रोत से कोई भी रोशनी न पाए। सोने से से कम एक घंटा पहले मोबाइल फोन,लैपटाप, टैबलेट और टीवी को बंद कर दें। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन उत्पादन को रोकने में सबसे आगे होती है। असल में रात का अंधेरा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि हमारे शरीर और दिल के लिए एक अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकता है। हमने आवश्यकता अपनी सुविधा के लिए इस अंधेरे पर जो रोशनी थोप दी है, वह हमारे जीवन को छोटा कर सकती है। हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि जैसे अच्छा भोजन और व्यायाम जरूरी है,वैसे ही गहरी और अंधेरी नींद भी हृदय के स्वास्थ्य की कुंजी है। अपने दिल को स्वस्थ रखने लिए हमें रातों को फिर से प्राकृतिक रूप में अपनाना होगा। यह छोटा सा बदलाव हमारे दिल को एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का मौका दे सकता है। याद रखना चाहिए कि जब बाहर की बत्तियां बुझती हैं, तभी हमारे भीतर जीवन की लौ अपनी पूरी क्षमता से जल पाती है।

गिग-वर्कर्स: डिजिटल सुविधा की चकाचौंध में पसीने का अंधेरा

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

ऑनलाइन बाजार और त्वरित सेवाओं के इस दौर में गिग-वर्कर्स शहरी जीवन-व्यवस्था की वह अदृश्य रीढ़ बन चुके हैं, जिनके बिना 'दस मिनट में डिलीवरी' और 'एक क्लिक पर सुविधा' की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाजार आने-जाने के झंझट से लोगों को मुक्त करने वाले ये युवा हर मौसम,हर समय और हर जोखिम में घर-घर सामान पहुँचाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जिनके श्रम पर डिजिटल अर्थव्यवस्था की ऊँची इमारत खड़ी है, वही श्रमिक सबसे अधिक असुरक्षा, शोषण और उपेक्षा झेल रहे हैं। नये साल की पूर्व संध्या पर गिग-वर्कर्स द्वारा की गई हड़ताल ने भले ही देशव्यापी आपूर्ति-श्रृंखला को ठप्प न किया हो, लेकिन इसने उनकी बदहाल कार्य-परिस्थितियों की ओर देश का ध्यान अवश्य खींचा है। यह हड़ताल किसी राजनीतिक उकसावे का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार बढ़ते काम के दबाव, घटते मेहनताने, नौकरी की अनिश्चितता और सम्मान के अभाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अपना व परिवार का पोषण करने वाले इन युवा गिग-वर्कर्स को अकसर सरपट दौड़ती मोटरसाइकिलों पर,भारी थैलों के साथ ऊँची इमारतों की सीढ़ियाँ चढ़ते देखा जा सकता है। समय सीमा का दबाव इतना तीव्र होता है कि जरा-सी देरी पर आर्थिक दंड झेलना पड़ता है। दुर्घटना, बीमारी या तकनीकी गड़बड़ी-किसी भी स्थिति में उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है। ग्राहकों का व्यवहार भी प्रायः असंवेदनशील होता है। देर होने पर झिड़कियाँ, सामान में कमी निकालकर अपमान, कभी-कभी हिंसक व्यवहार और रेटिंग के जरिये भविष्य की कमाई पर प्रहार-यह सब इनके रोजमर्रा का हिस्सा है। इसके बावजूद औसतन 12-14 घंटे काम करने के बाद भी सात-आठ सौ रुपये की आय और वह भी बिना समुचित बीमा या सामाजिक सुरक्षा के एक गहरे शोषण की ओर इशारा करती है।

गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं जो पारंपरिक नौकरी के बजाय अस्थायी,लचीले और स्वतंत्र रूप से छोटे-छोटे काम (गिग्स) करते हैं,जो अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ऊबर,स्वीग्गी, जोमाटोज् या अन्य ऐप्स के जरिए मिलते हैं और इन्हें प्रति कार्य या प्रोजेक्ट के हिसाब से भुगतान मिलता है,न कि नियमित वेतन. इन श्रमिकों के पास कोई स्थायी रोजगार अनुबंध नहीं होता और वे खुद के बॉस की तरह काम करते हैं,लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा (जैसे स्वास्थ्य बीमा,पेंशन) जैसे लाभ नहीं मिलते। गिग वर्कर्स की चुनौतियाँ एवं मजबूरियां ज्यादा है,आय कम। आय की अनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा लाभों (जैसे बीमारी,दुर्घटना,पेंशन) का अभाव,श्रम अधिक-भुगतान कम,कामकाजी घंटों और मजदूरी को लेकर अक्सर विवाद। गिग वर्कर्स गिग इकॉनमी का हिस्सा हैं,जहाँ वे अपनी मर्जी से छोटे-छोटे,अस्थायी काम करके पैसे कमाते हैं,जो पारंपरिक 9-से-5 की नौकरी से अलग होता है। गिग वर्कर का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर सेवा क्षेत्र में एक स्वतंत्र ठेकेदार या फ्रीलांसर के रूप में अस्थायी काम करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।

निःस्संदेह, गिग अर्थव्यवस्था ने रोजगार सृजन की अपनी क्षमता दिखाई है। आज भारत में गिग-वर्कर्स की संख्या सवा करोड़ से अधिक है और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या दो करोड़ पैंतीस लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बेरोजगारी के बढ़ते दौर में पढ़े-लिखे युवा इस व्यवस्था में 'विकल्प' के रूप में नहीं,बल्कि 'मजबूरी' में प्रवेश कर रहे हैं। जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है,वहाँ शिक्षित युवाओं का अस्थायी,असुरक्षित और सम्मानहीन श्रम-व्यवस्था में फँसना न केवल चिंताजनक, बल्कि शर्मनाक भी है। यह स्थिति बताती है कि हमारी विकास-नीतियाँ रोजगार की गुणवत्ता पर नहीं,केवल संख्या पर केंद्रित हैं। गिग-वर्कर्स की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कंपनियाँ उनसे पूरा काम लेती हैं, लेकिन उन्हें पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के दायरे में स्वीकार नहीं करतीं। उन्हें 'स्वतंत्र कामगार' कहकर नियुक्ति,स्थायित्व,बीमा और न्यूनतम वेतन जैसी जिम्मेदारियों से बचा जाता है।

हायर एंड फायर की नीति, एल्गोरिदम आधारित नियंत्रण, रेटिंग सिस्टम और प्रोत्साहन के नाम पर लालच-ये सब मिलकर एक ऐसी अदृश्य जकड़न पैदा करते हैं,जिसमें श्रमिक स्वतंत्र दिखता है,लेकिन वास्तव में पूरी तरह नियंत्रित होता है। हे ताल के दौरान भी अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर या ऑर्डर बढ़ाकर श्रमिक एकता को कमजोर कर दिया जाता है। 31 दिसंबर को एक प्रमुख खाद्य वितरण कंपनी द्वारा रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किया जाना इसी विडंबना को उजागर करता है। हाल के दिनों में संसद में भी गिग-वर्कर्स के शोषण का मुद्दा उठा है। सांसद राघव चड्ढा और मनोज कुमार झा जैसे नेताओं ने इस वर्ग की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिलाया है। यह स्वागतयोग्य है, क्योंकि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में जब तक इन श्रमिकों की आवाज शामिल नहीं होगी,तब तक सुधार अधूरे रहेंगे। भारत सरकार द्वारा हालिया श्रम सुधारों में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। एग्रीगेटर कंपनियों के टर्नओवर का एक से दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान, आधार से जुड़े सार्वभौमिक खाता नंबर जैसी व्यवस्थाएँ एक लंबे समय से प्रतीक्षित कदम हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रावधान वास्तव में गिग-वर्कर्स के जीवन में ठोस बदलाव ला पाएँगे? या फिर ये केवल कोड़ी सुधार बनकर रह जाएँगे? जब तक न्यूनतम आय,कार्य-घंटों की सीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक इन सुधारों को परिवर्तनकारी नहीं कहा जा सकता।

31 दिसंबर की हड़ताल भले ही पूरी तरह सफल न रही हो, लेकिन वह नैतिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह जाये थी। यह हे ताल व्यवस्था को बाधित करने से अधिक, व्यवस्था के भीतर छिपे अन्याय, शोषण की वृत्ति एवं दोगलेपन को उजागर करने का प्रयास थी। गिग-वर्कर्स ने यह संदेश दिया कि वे केवल 'डिलीवरी बॉय' नहीं, बल्कि श्रमशील नागरिक हैं, जिनके अधिकारों की अनदेखी अब और नहीं की जा सकती। निश्चित ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का भविष्य गिग-वर्कर्स के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह रूरी है कि नीति-निर्माता,कंपनियाँ और उपभोक्ता-तीनों अपनी भूमिका पर आत्ममंथन करें। कंपनियों को लाभ के साथ जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी, सरकार को कानूनों का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा और उपभोक्ताओं को सुविधा के साथ संवेदनशीलता भी अपनानी होगी। यदि हम गिग-वर्कर्स को केवल सुविधा का साधन मानते रहे और उन्हें सम्मान,सुरक्षा व स्थायित्व नहीं दिया,तो यह केवल श्रमिकों का नहीं,बल्कि हमारी विकास-कल्पना का भी संकट होगा। विकसित भारत,उन्नत भारत एवं समृद्ध भारत के नाम पर एक बदनुमा दाग होगा। डिजिटल भारत की असली परीक्षा यही है कि वह अपने सबसे तेज दौड़ वाले श्रमिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानित जीवन दे पाता है। तेजी से फैलती ऑनलाइन सेवाओं की दुनिया में गिग-वर्कर्स की कार्य-सेवाओं को अब अनौपचारिक एनहीं,बल्कि नियोजित, मान्यता प्राप्त और सम्मान जनक श्रम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी मेहनत का उचित और सुनिश्चित भुगतान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ और सामा जिक सुरक्षा कोई दया नहीं,बल्कि उनका अधिकार है,जिसमें सरकार को निर्णायक हस्तक्षेप करना ही होगा। मुनाफेकी अंधी दौड़ में लगी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को यह समझना होगा कि श्रम केवल लागत नहीं,बल्कि व्यवस्था की आत्मा है; शोषण की मानसिकता छोड़कर संवेदन शीलता और जवाबदेही अपनाए बिना कोई भी डिजिटल विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। यदि गिग-वर्क को गरिमा,सुरक्षा और स्थायित्व के साथ विकसित किया जाए, तो यही सेवाएँ मजबूरी का प्रतीक नहीं, बल्कि रो गार की एक आदर्श और मानवीय व्यवस्था बन सकती हैं,जहाँ सुविधा केवल उपभोक्ता को नहीं, सम्मान कामगार को भी मिले।

कविता

पल्लवी श्रीवास्तव
ममरखा,अरेराज,
पूर्वी चम्पारण
(बिहार)

औरत की ताकत

अगर पानी है कामयाबी,
तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है,कच्ची उम्र की अपनी ख्वाहिशों का, बलिदान करना पड़ता है।
टिकानी पड़ती है नज़र अपने लक्ष्य पर,
हिम्मत और हौसलों से हर मुश्किल को पार करना पड़ता है।
तोड़नी पड़ती हैं अंधविश्वास और गुलामी की ज़ंजीरें,
अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है।
कभी-कभी करना पड़ता है खुद को कुर्बान,
मिटाकर खुद को अपने मकसद के लिए,
एक नया इतिहास बनाना पड़ता है।
कब तक अंधविश्वास में खुद को यूँ ही मिटाती रहेगी?
खाकर ज़माने की ठोकरें,
जुल्म और अत्याचार सहती रहेगी?
कोई नहीं आएगा तुझे बचाने ,
कब तक इस भ्रम में अपनी हस्ती खोती रहेगी?
अपने सम्मान के लिए,
तुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। अपनी हिम्मत और ताकत का एहसास ज़माने को कराना पड़ेगा।
जिंदा हो अगर, तो ज़माने को ज़िंदा होने का एहसास कराना पड़ेगा।
कब तक यूँ ही सहती रहोगी,
जुल्म, अत्याचार और बलात्कार को?
इन सब को जड़ से मिटाना पड़ेगा ।
अब और इंतज़ार नहीं!
उठ, आवाज़ उठा,हिम्मत दिखा,अपनी इज़्ज़त और सम्मान,
तुझे खुद ही बचाना पड़ेगा।
तुझमें जो है ताकत और हिम्मत ,
उसका एहसास,ज़माने को कराना पड़ेगा।
लड़कर दुनिया के ज़ालिमों से,
खुद को बचाना पड़ेगा,
अपनी काबिलियत के दम पर,
खुद को सम्मान दिलाना पड़ेगा।
न तू अबला है,
न कमजोर,
तू खुद में एक शक्ति है,एक दौर है,
जो इतिहास बदलने का,हौंसला रखती है।
मत मिटा खुद को,
अंधविश्वास और अज्ञान की भट्टी में,तू कोई साधारण नहीं,
एक शक्ति है इस सृष्टि में।
तू झाँसी की रानी की वीरता रखती है,
माता सावित्रीबाई की शिक्षा और जागृति की ज्योति जलाती है,
माता रामबाई जैसी दृढ़ता और साहस से,
हक़ और इंसाफ़ दिलाने की ताकत रखती है।
फूलन देवी की तरह ,
जुल्म और अत्याचार के खिलाफ़ लड़कर,
ज़ालिमों को टकराने की हिम्मत ,
तेरे अंदर बसी है।
जिस दिन तुझे,अपनी जिंदा होने का पूरा एहसास हो जाएगा,
उसी दिन तेरे हौसले,जुनून और हिम्मत से एक नया इतिहास लिखा जाएगा।
तेरे भीतर है वो आग,
जो अन्याय को राख में बदल सकती है।
बस पहचान ले अपनी शक्ति को,
क्योंकि तू "औरत की ताकत" रखती है।
तू जननी है इस जग की,
तू दुनिया को बदलने की ताकत रखती है।

कोई किसी को सिखा नहीं सकता है जब खुद में इच्छा जागती है तभी कोई सीख पाता है ।

~ -श्री अरबिंदो ~

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

C M Y K

सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ में कलेक्टर ने यातायात नियमों के पालन पर जोर दिया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के यातायात थाने के पास सरगुजा पुलिस द्वारा शुक्रवार को आयोजित सडक़ सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत ने सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों के पालन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि लोग यातायात नियमों का अनुशासित तरीके से पालन करें और इस दिशा में समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है।

इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि एक महीने तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरुकता रथ जाएगा,जो लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर हर साल सडक़ दुर्घटनाओं की समीक्षा की जाती है और चार मुख्य कारण सामने आए हैं, जिनकी वजह से अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं।

पहला कारण है बाइक पर तीन सवारी बैठाना,जो सडक़ दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनता है। दूसरा कारण है दो पहिया वाहन चालकों का हेलमेट न पहनना। इसके अलावा ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने की आदत भी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इन चार मुख्य मुद्दों पर जागरुकता रथ के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा ताकि वे सडक़ सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दुर्घटनाओं में कमी आए। एसपी ने कहा कि इस सडक़ सुरक्षा माह का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देना है ताकि वे सडक़ों पर सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें और दुर्घटनाओं से बच सकें।

इस अभियान का लक्ष्य सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को यह समझाना है कि यातायात नियमों का पालन उनकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने इस आयोजन के सफल संचालन के लिए उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का मंच संचालन सुनीता दास, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सीएसपी राहुल बंसल, सहायक आयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विनय सोनी, नवा विहान के संयोजक मंगल पांडेय, और समन्वयक अनिल मिश्रा भी उपस्थित रहे।

सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में आई कमी

पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया कि 2025 में सडक़ दुर्घटनाओं और इससे होने वाली मौतों में निश्चित तौर पर कमी आई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में जिले में 614 सडक़ दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 354 लोगों की मौत हुई थी,जबकि 2025 में सडक़ दुर्घटनाओं की संख्या 598 रही और इनमें 302 मौतें हुईं। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सडक़ सुरक्षा माह के तहत किए गए जागरूकता अभियानों का सकारात्मक असर पड़ा है। इस प्रकार, सरगुजा पुलिस द्वारा आयोजित सडक़ सुरक्षा माह का यह आयोजन सडक़ सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता लाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

सरगुजा वन मंडल में 300 वन प्रबंधन समितियों की बैठक आयोजित

वन संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता एवं स्थानीय सहभागिता पर दिया गया विशेष जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

नव वर्ष के अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में 02 जनवरी 2026 को सरगुजा वन मंडल अंतर्गत 300 वन प्रबंधन समितियों (जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना रहा।

बैठक के दौरान वन एवं वन्यजीव अपराधों में कमी लाने के प्रभावी उपायों,वनाग्नि की रोकथाम, अतिक्रमण पर नियंत्रण एवं वन संपदा के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन तथा हाथियों एवं अन्य वन्यजीवों के व्यवहार से संबंधित आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी भी साझा की गई। इको-पर्यटन के विकास एवं संरक्षण पर विशेष बल देते हुए स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही वन विभाग द्वारा संचालित आयमूलक गतिविधियों,गौण वन उपज के सतत संग्रहण,वन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे विषयों को भी प्रमुखता से रखा गया। वन प्रबंधन समितियाँ सहभागी वन प्रबंधन की एक सशक्त कड़ी हैं,जिनके माध्यम से वन संरक्षण,संसाधनों का सतत उपयोग एवं ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलती है,जिससे वन प्रबंधन को अधिक प्रभावी,पारदर्शी एवं दीर्घकालिक बनाया जा सके।

अवैध धान भंडारण पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई,लगभग 24 क्विंटल (600 बोरा) धान जप्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड बतौली के ग्राम कपाटबहरी में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विशुनपुर क्षेत्र के किसान श्री इमरान इराकी,निवासी सीतापुर का लगभग 24 क्विंटल (600 बोरा) धान ग्राम कपाटबहरी में श्री प्रफुल एक्का के घर में अवैध रूप से भंडारित पाया गया। जांच उपरांत नियमानुसार धान को जप्त किया गया तथा जिस व्यक्ति के घर में धान पाया गया है,उसी को सुपुर्द किया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री वसंत ने धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने आमजन एवं किसानों से अपील की है कि धान विक्रय एवं भंडारण से संबंधित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। शासन की पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

संविधान,सद्भाव और सामाजिक न्याय ही भारत की आत्मा : टीएस सिंहदेव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने नववर्ष 2026 के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कहा कि भारत की मूल आत्मा सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता में निहित है। उन्होंने कहा कि बीता हुआ वर्ष 2025 सामाजिक चेतना के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, विशेषकर आदिवासी अंचलों में बढ़ते वैमनस्य और टकराव की घटनाएँ छत्तीसगढ़ की शांति-प्रिय परंपरा के विपरीत हैं। सिंहदेव ने स्पष्ट किया कि उनका यह वक्तव्य किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक संवैधानिक नागरिक और जनसेवक के रूप में है। उन्होंने बाबा साहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर के विचारों का स्मरण करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की आत्मा समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) और पहचान आधारित अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि ऐसी घटनाएँ न केवल मानवता पर आघात हैं,बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर करती हैं। उन्होंने कहा कि भय,अफवाह और नफरत के आधार पर निर्मित राजनीति समाज को विभाजित करती है और विकास की गति को बाधित करती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोपरि है और प्रशासन की निष्पक्षता ही जनता के विश्वास की नींव है। श्री सिंहदेव ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक दबाव से मुक्त होकर केवल संविधान के अनुरूप कार्य करें। युवाओं से विशेष संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना-क्रांति के इस युग में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे भ्रामक सूचनाओं और नफरत फैलाने वाली विचारधाराओं से दूर रहकर संवाद,संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी के सेतु बनें। अपने संदेश के अंत में श्री सिंहदेव ने कहा कि वर्ष 2026 में हमें मिलकर विभाजन की राजनीति को नकारते हुए शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता जैसे मूल मुद्दों पर केंद्रित एक समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढना होगा।

कार्य मे लापरवाही पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पर हुई कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

बाल विकास परियोजना उदयपुर अंतर्गत सेक्टर डांडगांव के आंगनबाड़ी केन्द्र चारपारा-सलवा एवं डांडगांव बाजारपारा के सम्बंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जे आर प्रधान द्वारा केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र चारपारा-सलवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित पाई गई,परन्तु केन्द्र में एक भी हितग्राही उपस्थित नहीं पाए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केन्द्र डाडगाव हरिजनपारा बाजारपारा के निरीक्षण के

दौरान केन्द्र बंद पाया गया,साथ ही कार्यकर्ता एवं सहायिका केन्द्र में उपस्थित नही पाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि कार्यकर्ता नियमित रूप से केन्द्र नही आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रेडी टू ईट फूड एव गर्म भोजन भी नियमित प्रदाय नहीं किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र मे मिलने वाली रेडी टू ईट फूड एवं गर्म भोजन की सामग्री को कार्यकर्ता अपने घर पर रखती हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी सहायिका बच्चों को बुलाने नहीं जाती हैं। निरीक्षण के दौरान शिशुवती महिला से भी

चर्चा की गयी। महिला द्वारा बताया गया कि उन्हें नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में रेडी टू ईट प्राप्त नही होता है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों से भी चर्चा की गयी, उनके द्वारा बताया गया कि उनके बच्चों के लिए भी रेडी टू ईट नहीं मिलता है। उक्त शिकायतों के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता को पद से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है एवं आंगनबाड़ी सहायिका को चेतावनी पत्र तथा सेक्टर सुपरवाईजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

किसानों के हित में प्रशासन सतर्क...सतत् निगरानी से अंतर्राज्यीय अवैध धान तस्करों पर प्रभावी कार्यवाही

-संवाददाता-
बलरामपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

गत रात्रि राजस्व एवं पुलिस बल के संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय धान तस्करों द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 0199 के माध्यम से धान तस्करी किया जा रहा था। वाहन में 60 बोरी अवैध धान लोड था। पूछताछ करने पर उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के धान तस्करी में पाये गये कोचिये श्रवण कुमार,कृष्ण मोहन कुमार,विनय कुमार गुप्ता,राजदेव गुप्ता,राधेश्याम गुप्ता, सत्यदेव गुप्ता,मनोज कुमार सभी सागोबांध,थाना बभनी, जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश एवं विकास ग्राम त्रिशुली थाना सनावल व विंध्याचल गुप्ता ग्राम पचावल थाना सनावल जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़ की संलिप्तता पायी गयी। अंतर्राज्यीय गिरोह धान तस्करी में पाये गए श्रवण, कृष्णमोहन एवं विकास को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है तथा इस कार्य में सहयोग मुखबीरी किये जाने वाले व्यक्ति विनय गुप्ता, राजदेव गुप्ता,राधेश्याम गुप्ता,मनोज

गुप्ता, को तत्काल 170,126,135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। शेष 02 सहयोगी विंध्याचल गुप्ता एवं सत्यदेव गुप्ता को जो अपराधियों को छुड़ाने आये थे, उनके विरूद्ध धारा 126,135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाउण्ड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है।

जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन पर संयुक्त दलों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत पूर्व में विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के अंतर्गत ग्राम कुर्लडीह निवासी श्याम सुन्दर गुप्ता के द्वारा अवैध धान परिवहन करने एवं किसानों के विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों का दुरूपयोग करने पर 3, 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। प्रशासन की सतर्क एवं प्रभावी कार्यवाही से क्षेत्र में धान उपार्जन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है। सूचना तंत्र को व्यापक रूप से मजबूत किए जाने के परिणाम स्वरूप अवैध धान परिवहन एवं अनियमित गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। जिसमें अब तक जिले में कुल 118 प्रकरण में 14,173.29 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान अवैध परिवहन में प्रयुक्त 65 चार पहिया तथा 10 दोपहिया सहित कुल 75 वाहनों को जब्त किया गया है और 4 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है, जिससे किसानों में विश्वास का वातावरण बना है और समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो रही है। प्रशासन द्वारा गाँव-गाँव में वालंटियर्स का गठन किया गया है, जो धान उपार्जन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। धान खरीदी से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए संपर्क नम्बर 9343130794 पर सूचना दे सकते है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दे सकते हैं। जिसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधि की सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, जिससे जनभागीदारी के माध्यम से धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य में देरी पर किया असंतोष व्यक्त सीजीएमएससी को शीघ्र प्रगति के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दरिमा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट सहित अन्य भवनों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया तथा निर्माण एजेंसी सीजीएमएससी को कार्य में तत्काल प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही यहां ऑपरेशन थियेटर (ओटी) को शीघ्र फंक्शनल किया जाए। इसके लिए ऑपरेशन थियेटर में आवश्यक उपकरणों की मांग राज्य कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री वसंत ने दवाईयों की उपलब्धता की जानकारी ली तथा कहा कि मरीजों को समय पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हों। उन्होंने संस्थागत प्रसव में महिलाओं को प्रदान किए जाने वाली 1400 रुपए की सहायता राशि समय पर दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा कहा कि कोई भी प्रकरण लंबित ना रहे। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी-कर्मचारी समय पर उपस्थित रहें, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धितों पर कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मरीजों को प्रदाय किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा संस्था प्रभारी को निर्देशित किया गया कि मरीजों को निर्धारित मीनू के अनुसार ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त रामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं बड़ा दामली क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी की जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर आवश्यक पदों की पूर्ति सुनिश्चित करने तथा शेष पदों की मांग राज्य कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

पति व बेटी ने शराब पीने की आदी महिला को पीट-पीटकर की हत्या

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के घुटरापारा में 29 दिसंबर की शाम को शराब पीने के आदि महिला को उसके पति व बेटी ने डंडे से बदम पिटाई कर दी। महिला जख्मी हालत में पूरी रात घर में पड़ी रही। दूसर दिन उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता व पुत्री को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दुर्गा हरि पति धन्नू हरि उम्र 44 वर्ष कोतवाली क्षेत्र के घुटरापारा की रहने वाली थी। वह शराब पीने की आदि थी। वह शराब के नशे में अक्सर वह कहीं चली जाती थी और रूक जाती थी। इससे उसका पति व घर वाले परेशान रहते थे। 21-22 दिसंबर को दुर्गा घर में बिना बताए कहीं चली गई थी। परेशान पति ने खोजबीन की पर पता नहीं चलने पर वह अपने ससुराल नमनाकला फोन लगाकर पूछा तो उसे वहां नहीं आने की बात कही गई। 29 दिसंबर की शाम को महिला शराब के नशे में घर पहुंची। एक सप्ताह तक गायब रहने व शराब पीने को लेकर घर में विवाद हुआ। पति धन्नू हरि व बेटी सोनामती ने मिलकर डंडे से उसकी बेदम पिटाई कर दी। पति व

बेटी द्वारा मारपीट किए जाने से महिला बेहोश हो गई और पूरी रात घर में जख्मी हालात में पड़ी रही। दूसरे दिन तबियत बिगडऩे पर परिजन उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान 30 दिसंबर को ही मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मिशन अस्पताल पुलिस सहायता केन्द्र द्वारा मामले में मर्ग कायम कर जांच के लिए कोतवाली भोजा गया था।

लायंस क्लब ने जरूरतमंदों के बीच वितरण किए कंबल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के लायंस क्लब अंबिकापुर सरगुजा द्वारा 31 दिसंबर की रात्रि में नववर्ष के आगमन पर ठंड से ठिठुरते हुए लोगों को कंबल ओढ़ाने का कार्य प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। क्लब सदस्यों द्वारा परस्पर एकत्रित किए गए कंबल गुरु नानक चौक, स्कूल रोड, देवीगंज रोड, सदर रोड, विवेकानंद चौक, स्टेडियम के पास और गांधी चौक में ठंड से ठिठुरते हुए लोगों को ओढाये गये, जिसमें सबसे अधिक स्टेडियम के पास ठंड से कांपते हुए लोग पाये गए।

निधन

अम्बिकापुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। अग्निशमन विभाग में पदस्थ प्रतापपुर रोड निवासी प्रमोद मिश्रा की धर्मपत्नी श्रीमती आनन्दी मिश्रा का निधन हो गया,वे 56 वर्ष की थीं। उनका रायपुर के एमएमआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे अपने पीछे एक पुत्र कुंदन मिश्रा और पुत्री पायल मिश्रा सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गईं। श्रीमती आनन्दी मिश्रा गौरी मंदिर के पुजारी पंडित राजेश मिश्रा की भाभी थीं। घटना से मोहल्ले में शोक का माहौल है। शुक्रवार को अंबिकापुर के शंकर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया,जिसमें काफी संख्या में गणमान्यजनों के अलावा अग्निशमन विभाग,नगर निगम के कर्मचारी-अधिकारी शामिल हुए। मुखाग्नि पति प्रमोद मिश्रा ने दी।

CMYK

यमन में सऊदी अरब का हवाई हमला,7 की मौत

सरकार-अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी,सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया

सना,02 जनवरी 2026। यमन में सऊदी अरब की एयरस्ट्राइक में 7 अलगाववादी लड़ाकों की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार को दक्षिणी प्रांत के हद्रामौत में हुई जहां अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के एक ठिकाने को निशाना बनाया गया। इसमें 20 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। इस बीच यमन सरकार ने सैन्य कार्रवाई कर अलगाववादी गुट से अहम मिलिट्री बेस वापस अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। हद्रामौत के गवर्नर सालेम अल-खानबाशी ने कहा कि सुरक्षाबल सिर्फ सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के कब्जे से सैन्य ठिकानों को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन का एक अलगाववादी संगठन है, जो कि यमन के दक्षिणी हिस्से को आजाद कराने के लिए जंग लड़ रहा है। इस संगठन कोयूएई का समर्थन मिलता है।

सऊदी ने यमन के मुकल्ला पोर्ट को निशाना बनाया : सऊदी अरब ने मंगलवार सुबह यमन के मुकल्ला पोर्ट पर बमबारी की थी। उसने आरोप लगाया था कि यूएई के फुजैरा पोर्ट से आए दो जहाजों से यहां हथियार और सैन्य वाहन उतारे जा रहे थे। इन जहाजों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद थे। सऊदी अरब का कहना है कि ये हथियार सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल नाम के अलगाववादी गुट को दिए जा रहे थे, जो कि शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वायुसेना ने सीमित हवाई हमला कर हथियारों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया सऊदी अरब और यूएई पिछले 10 साल से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन वे वहां अलग-अलग गुटों का समर्थन करते हैं।

यमन ने यूएई से डिफेंस डील रद्द की : मुकल्ला पर हुए हवाई हमले के बाद यमन सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया रक्षा समझौता भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने हालात पर नियंत्रण के लिए 72 घंटे की हवाई,थल और समुद्री नाकाबंदी लागू करने और 90 दिनों के लिए आपातकाल घोषित करने का फैसला किया है।

सऊदी ने यमन पर हमला क्यों किया : सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल) एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है, जिसेयूएई का समर्थन प्राप्त है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण दो अलग देशों में बांटना है। इसके बाद वह दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना चाहता है। यमन 1990 से पहले दो हिस्सों उत्तरी और दक्षिणी यमन में बंटा हुआ था। दोनों के एकीकरण के बाद भी दक्षिण में अलगाव की भावना बरकरार है। पिछले एक महीने में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने यमन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाए थे। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की फौजों ने हद्रामौत और अल-महा जैसे तेल और गैस-समृद्ध इलाकों पर कब्जा कर लिया।

इस वजह से यमन सरकार की सुरक्षा बलों और स्थानीय कबीलों को पीछे हटना पड़ा। कई इलाकों में हिंसा और मौतों की खबरें आई दिसंबर के मध्य तक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने कई अहम तेल और गैस क्षेत्रों पर नियंत्रण का दावा किया।

दक्षिणी अबयान प्रांत में नए सैन्य अभियान की घोषणा की। 15 दिसंबर को सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अबयान के पहाड़ी इलाकों में बड़ा हमला किया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने हद्रामौत के वादी नहाब इलाके में चेतावनी के तौर पर हवाई हमले किए। सऊदी ने साफ कहा कि अगर सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पीछे नहीं हटा, तो आगे और कड़ी कार्रवाई होगी। मुकल्ला पोर्ट पर हमला उसी चेतावनी की अगली कड़ी माना जा रहा है।

रूस ने यूक्रेन के 64 ड्रोन मार गिराए दो हमलावर समूह का सफाया किया

मॉस्को,02 जनवरी 2026। रूसी वायु रक्षा प्रणाली (एयर डिफेंस सिस्टम) ने 64 यूक्रेनी ड्रोन को रोका और नष्ट कर दिया। इसके अलावा रूसी सेना ने दो यूक्रेनी हमलावर समू को खत्म कर दिया। उन्होंने सूमी क्षेत्र में ग्राबोवस्कोये बस्ती के पास जवाबी हमला करने की कोशिश की थी। बेलगोरोड के क्षेत्रीय संकट केंद्र ने एक बयान में कहा कि पिछले दिनों यूक्रेनी सेना ने रूस के सीमावर्ती बेलगोरोड क्षेत्र के रिहायशी इलाकों पर 80 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की एक रिपोर्ट के अनुसार,रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पिछली रात रूसी एयर डिफेंस ने सारातोव क्षेत्र में यूक्रेन के 20 फिक्स्ड-विंग मानवरहित हवाई वाहन गिराए गए। इसके अलावा वोरोनेज और सारातोव क्षेत्रों में से प्रत्येक में आठ ड्रोन, मॉस्को क्षेत्र में सात ड्रोन, रियाजान और रोस्तोव क्षेत्रों में से प्रत्येक में छह ड्रोन,तुला क्षेत्र में तीन ड्रोन,बेलगोरोड क्षेत्र में दो ड्रोन, और कुर्स्क,पेन्जा,कलुगा व तांबोव क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक-एक ड्रोन नष्ट किया गया। रक्षा सूत्रों के अनुसार, रूसी सेना ने दो यूक्रेनी हमलावर समूह को खत्म कर दिया। सूमी क्षेत्र में ग्राबोवस्कोये इलाके में यूक्रेनी सेना ने 119वीं अलग टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड के दो हमलावर समूह के साथ जवाबी हमला किया। इस हमले को गोलाबारी से नाकाम कर दिया गया और दुश्मन के दोनों समूह को खत्म कर दिया गया। उधर,बेलगोरोड के क्षेत्रीय संकट केंद्र ने पहली

जनवरी को बयान में कहा कि पिछले दिन यूक्रेनी सेना ने रूस के सीमावर्ती बेलगोरोड क्षेत्र में रिहायशी इलाकों पर 80 से ज्यादा ड्रोन दागे। इससे क्रास्नी ओक्ट्याब्र गांव में एक कृषि सुविधा की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि यास्ने जोरी गांव में एक इमारत,एक कार और एक निजी घर को नुकसान पहुंचा। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग चौथे वर्ष में प्रवेश कर गई है। नए साल की शुरुआत दोनों देशों के बीच हमलों और तेज कूटनीतिक हलचलों के साथ हुई है। रूस ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए 200 से अधिक ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र के एक होटल में 24 लोग मारे गए।

ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन मुर्दाबाद के नारे लगे,हिंसा में 7 मौतें

तेहरान,02 जनवरी 2026। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी है। इनमें अब तक 6 आम लोगों और 1 सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो चुकी है। मारे गए प्रदर्शनकारियों के अंतिम संस्कार में लोगों ने 'डेथ टू खामेनेई' यानी खामेनई मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन ईरान के पवित्र शहर कोम तक फैल गए हैं। कोम शिया धर्मगुरुओं का एक प्रमुख गढ़ है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार,भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राजशाही के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 1 जनवरी को 5 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 31 दिसंबर को भी एक शख्स की प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मौत हो गई थी। ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी। तब राजधानी तेहरान में व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसमें हजारों GenZ भी शामिल हो चुके हैं।

ट्रम्प बोले- प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए तैयार : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी। ट्रम्प ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रुथ सोशल पर ट्रम्प ने लिखा, 'अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है या उन्हें बेरहमी से मारता है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ' इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी की तरफ से किसी भी हमले की स्थिति में उसके बेस को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने शुक्रवार को कहा है कि अगर अमेरिका आक्रामक कदम उठाता है तो उसके सैन्य ठिकानों को वैध निशाना माना जाएगा। इससे पहले अमेरिका, ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं पर हमलें कर चुका है। जून 2025 में ईरान-इजराइल के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था।

ईरान में महंगाई से आम लोगों में नाराजगी बढ़ी : देशभर में GenZ आक्रोश में है। इसका कारण आर्थिक बदहाली रहा है। दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। साल की शुरुआत से रियाल की कीमत लगभग आधी हो चुकी है। यहां महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है।

व्यापार समाचार

मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार,निफ्टी ने बनाया ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड

सेंसेक्स 573 अंक चढ़कर 85,762 पर बंद,निफ्टी 26340 के स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट, रुपये की मजबूती, घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी तथा ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों के साथ ही लार्ज कैप शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी के कारण घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शानदार मजबूती के साथ बंद हुआ। शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया,जिसके कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आ गई। हालांकि दोपहर 2 बजे के बाद मुनाफा वसूली के चक्कर में हुई बिकवाली के कारण बाजार की चाल में मामूली गिरावट भी आई, लेकिन शाम 3 बजे के थोड़ी देर पहले ही खरीदारों ने एक बार फिर लिवाली का जोर बना दिया, जिससे दोनों सूचकांकों की चाल में एक बार फिर तेजी आ गई। शुक्रवार को तेजी के कारण निफ्टी ऑल टाइम हाई का नया रिकार्ड बनाने में भी सफल रहा। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.67 प्रतिशत और निफ्टी 0.70 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। शुक्रवार को दिनभर के कारोबार के दौरान बैंकिंग,पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में जम कर खरीदारी होती रही।इसी तरह ऑटोमोबाइल,मेटल,इंफ्रास्ट्रक्चर,कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, हेल्थकेयर,ऑयल एंड गैस तथा टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में शुक्रवार को बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी शुक्रवार को लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.97 प्रतिशत की

मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.79 प्रतिशत की तेजी के साथ शुक्रवार को कारोबार का अंत किया। शुक्रवार को शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में सवा चार लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार को कारोबार के बाद बढ़ कर 481.29 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 476.92 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को शुक्रवार को कारोबार से करीब 4.37 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। शुक्रवार को दिनभर के कारोबार में बीएसई में 4,371 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 2,773 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1,449 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 149 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में शुक्रवार को 2,861 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 2,045 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान और 816 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 25 शेयर बढ़त के साथ और 5 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 39 शेयर हरे निशान में और 11 शेयर लाल निशान में बंद हुए।

बीएसई का सेंसेक्स शुक्रवार को 70.76 अंक की मामूली मजबूती के साथ 85,259.36 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के कुछ देर बाद खरीदारी का जोर बन जाने के कारण इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई। दोपहर 2 बजे तक लगातार खरीदारी होने के बाद मुनाफा वसूली के चक्कर में कुछ देर के लिए बिकवाली का दबाव भी बना,जिससे सेंसेक्स की चाल में मामूली गिरावट आई। हालांकि थोड़ी ही देर बाद खरीदारों ने दोबारा लिवाली का जोर बना दिया,जिससे शुक्रवार को कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 623.67 अंक उछल कर 85,812.27 अंक के स्तर तक पहुंच गया। अंत में इंट्रा-डे सेटलमेंट के कारण हुई मामूली बिकवाली की वजह से सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 50 अंक लुढ़क कर 573.41 अंक की बढ़त के साथ 85,762.01 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह एनएसई के निफ्टी ने शुक्रवार को 8.55 अंक की मामूली तेजी के साथ 26,155.10 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के कुछ देर बाद तेजड़ियों ने एक्टिव होकर खरीदारी शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक ने कुलांचे भरना शुरू कर दिया।

स्टॉक मार्केट में ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन की जोरदार एंट्री,लिस्टिंग के बाद लगा अपर सर्किट

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। रेलवे के लिए काम करने वाली कंपनी ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा के शेयरों ने शुक्रवार को स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 174 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 90 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 330.60 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से इस शेयर की चाल में और तेजी आ गई,जिससे थोड़ी ही देर में ये 347.10 रुपये के अपर सर्किट लेवल तक पहुंच गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 99.48 प्रतिशत का मुनाफा हो चुका है।

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा का 84.22 करोड़ रुपये का आईपीओ 26 से 30 दिसंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 526.56 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स

(क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 236.30 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 872.09 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 544.28 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 48,40,000 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 8.15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 10.26 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 13.99 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें, 2025-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान कंपनी को 7.49 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हो चुका है।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना,चांदी के भाव में गिरावट जारी

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार तीन दिन तक गिरावट का सामना करने के बाद सोने के भाव में शुक्रवार को तेजी का रुख नजर आ रहा है। हालांकि चांदी के भाव में शुक्रवार को भी गिरावट जारी है। कीमत में आई तेजी के कारण सर्राफा बाजार में शुक्रवार को हाजिर सोना 170 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 190 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। दाम चढ़ने के बाद देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना शुक्रवार को 1,35,070 रुपये से लेकर 1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना शुक्रवार को 1,23,810 रुपये से लेकर 1,23,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं भाव में गिरावट जारी रहने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी एक हजार रुपये सस्ती हो गई है। कीमत में आई इस गिरावट के कारण दिल्ली में ये चमकीली धातु शुक्रवार को 2,37,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है। दिल्ली में शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 1,35,220 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है,जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,35,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,35,120 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना शुक्रवार को 1,35,070 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,23,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,35,070 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,35,120 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है,जबकि 22 कैरेट सोना 1,23,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना शुक्रवार को 1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,23,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,35,120 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,23,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के

स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,23,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक,तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी शुक्रवार को सोने के भाव में तेजी आई है।

पदोन्नति के बाद भी प्रभार नहीं छात्रावास अधीक्षक 'बिना काम'

आदिवासी विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल,कर्मचारियों में बढ़ता असंतोष

-रवि सिंह-

कोरिया,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। कार्यालय आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास से पदोन्नति प्राप्त कर छात्रावास अधीक्षक बने कर्मचारियों के लिए यह समय उपलब्धि का होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इसके उलट है,पदोन्नति आदेश जारी होने और नई पदस्थापना पर जॉइनिंग दिए हुए दो माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिले के कई छात्रावास अधीक्षकों को अब तक संबंधित छात्रावासों का वास्तविक प्रभार (चार्ज) नहीं सौंपा गया है,नतीजा यह है कि पदोन्नत अधिकारी कार्यालय तो पहुंच रहे हैं,लेकिन न तो उन्हें काम सौंपा गया है और न ही अधिकार,जिससे वे मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति में हैं,छात्रावासों से सीधे तौर पर आदिवासी और वंचित वर्ग के बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। ऐसे में अधीक्षकों को अधिकारहीन बनाकर बैठा देना न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय है,बल्कि छात्रावास प्रबंधन और विद्यार्थियों के हितों के लिए भी नुकसानदेह है, अब निगाहें जिला प्रशासन और विभागीय उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं क्या वे समय रहते हस्तक्षेप कर पदोन्नत अधीक्षकों को उनका वैधानिक प्रभार सौंपेंगे,या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?

नियमों के उलट चल रही व्यवस्था

प्रशासनिक नियमों के अनुसार,पदोन्नति के बाद जॉइनिंग के साथ ही संबंधित संस्था का प्रभार मिल जाना चाहिए। लेकिन कोरिया जिले में स्थिति उलटी दिखाई दे रही है कई छात्रावासों में पुराने अधीक्षक या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यरत कर्मचारी अभी भी प्रभार संभाले हुए हैं,कहीं प्रभार छोड़ने में आनाकानी है, तो कहीं फाइलें प्रशासनिक सुस्ती की भेंट चढ़ी हुई हैं, इस असमंजस का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही,किसी भी अव्यवस्था की जवाबदेही अस्पष्ट बनी हुई है,पदोन्नत अधिकारी निर्णय लेने में असमर्थ हैं।

कर्मचारियों में बढ़ती नाराजगी : पदोन्नत अधीक्षकों में इस देरी को लेकर गहरी नाराजगी है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधीक्षक ने बताया हमने दो महीने पहले जॉइनिंग दे दी, लेकिन आज तक लिखित में प्रभार नहीं मिला। बिना प्रभार हम न तो वित्तीय निर्णय ले सकते हैं और न ही प्रशासनिक। यह हमारी वरिष्ठता और मनोबल दोनों पर सीधा आघात है, अधीक्षकों का कहना है कि प्रभार को लेकर बार-बार पूछने पर सिर्फ 'आज-कल हो जाएगा' कहकर टाल दिया जाता है।

विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल : इस पूरे घटनाक्रम ने आदिवासी विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं,क्या पदोन्नति केवल कागज़ी प्रक्रिया बनकर रह गई है? क्या जानबूझकर प्रभार रोका जा रहा है? क्या इससे विभागीय मनमानी और दबाव की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है?

मूल पद के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया जा रहा प्रभार?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पदोन्नत अधीक्षक उपलब्ध हैं,तो मूल पद के कर्मचारियों को प्रभार न देकर दूसरे कर्मचारियों से काम क्यों कराया जा रहा है? लब्जी,तेलीमुड़ा,घुघरा, कटगोड़ी सहित कई छात्रावास ऐसे हैं, जहां पदोन्नत अधीक्षक जॉइनिंग दे चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक प्रभार नहीं सौंपा गया, सूत्रों के अनुसार, इस देरी के पीछे केवल लापरवाही नहीं, बल्कि जिला कार्यालय से जुड़ा एक 'लंबा खेल' बताया जा रहा है। इसी कारण कभी तकनीकी बहाना, तो कभी प्रशासनिक कारण बताकर मामला टाला जा रहा है।

छत्तीसगढ़ रजत जयंती का भव्य उत्सवरू जिले में रजत जयंती चावल उत्सव का ऐतिहासिक शुभारंभ

जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में शुरू हुआ रजत जयंती चावल उत्सव,09 जनवरी तक चलेगा जनकल्याण का महाअभियान

-संवाददाता-

एमसीबी,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। जिले में छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर रजत जयंती चावल उत्सव का आज 02 जनवरी 2026 से भव्य एवं गरिमामय शुभारंभ किया गया,जो 09 जनवरी 2026 तक जिले भर में आयोजित किया जाएगा। खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस अवधि को विभागीय गतिविधियों के विशेष सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला खाद्य अधिकारी एवं समस्त खाद्य निरीक्षकों की उपस्थिति में किया गया,जिसमें जिले के विभिन्न जनप्रतिनिधि भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। रजत जयंती चावल उत्सव के दौरान जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, निगरानी समिति के सदस्यों,दुकान संचालकों एवं बड़ी संख्या में हितग्राहियों की सहभागिता के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से आयोजन को विशेष गरिमा प्राप्त हुई तथा आम नागरिकों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ। उत्सव के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने का संदेश दिया गया। विशेष सप्ताह के अंतर्गत शेष राशन कार्ड धारियों एवं हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है,ताकि सभी पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित सूचना बोर्ड, स्टॉक पंजी,वितरण पंजी एवं चावल उत्सव पंजी को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं,जिससे रिकॉर्ड संधारण में पारदर्शिता बनी रहे। रजत जयंती चावल उत्सव के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित प्रारूप में बैनर प्रिंट कर समस्त उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित किए गए हैं तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मुनादी के माध्यम से आमजन को जानकारी दी जा रही है। आयोजन से संबंधित समस्त गतिविधियों के फोटोग्राफ संकलित कर विभागीय कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में रजत जयंती चावल उत्सव शासन, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से एक जनउत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।

सहायक ग्रेड 2 तीर्थाराम साहू को उनके सेवानिवृत्ति पर दी गई भावभीनी विदाई

-संवाददाता-

जशपुरनगर, 02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। कलेक्टोरेट कार्यालय जशपुर में पदस्थ रहे सहायक ग्रेड-2 तीर्थाराम साहू के सेवानिवृत्त होने पर कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में एक आत्मीय एवं भावनात्मक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, एसडीएम विश्वासराव मस्के सहित कलेक्टोरेट कार्यालय के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने प्रिय सहकर्मी को पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल भेंट एवं माल्यार्पण कर सम्मान पूर्वक विदाई दी।

समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने साहू के लंबे सेवाकाल को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में सदैव ईमानदारी, समयबद्धता और निष्ठा का परिचय दिया। सामान्य प्रशासनिक कार्यों से लेकर जटिल फाइल प्रबंधन तक, उनकी कार्यशैली अनुकरणीय रही है। कार्यालय में उनका शांत स्वभाव, सहयोगी दृष्टिकोण और हर कर्मचारी की सहायता के लिए तत्पर रहना उन्हें सभी के बीच अत्यंत प्रिय बनाता रहा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप साहू ने कहा कि तीर्थाराम साहू केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि कार्यालय की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से अनेक नव पदस्थ कर्मचारियों को सीखने का अवसर मिला। सहायक कलेक्टर अनिकेत अशोक ने कहा कि उनके सेवानिवृत्त होने से कलेक्ट्रेट परिवार को एक अनुभवी मार्गदर्शक की कमी खलेगी। विदाई समारोह के दौरान तीर्थाराम साहू भावुक नजर आए और उन्होंने सभी अधिकारियों एवं सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय उनके लिए केवल कार्यस्थल नहीं बल्कि एक परिवार रहा है। उन्होंने अपने सेवाकाल की स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ही वे अपने दायित्वों का सफल निर्वहन कर पाए। इस अवसर पर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अपनापन, सम्मान और कृतज्ञता का वातावरण देखने को मिला। तीर्थाराम साहू के सेवानिवृत्त होने के साथ ही प्रशासनिक सेवा का एक समर्पित अध्याय पूर्ण हुआ, जिसे कार्यालय परिवार सदैव गर्व के साथ स्मरण करता रहेगा।

जिले में 5 करोड़ 22 लाख की लागत से बनेंगे 18 महतारी सदन,ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का बनेंगे केंद्र

-संवाददाता-

जशपुरनगर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले की ग्रामीण महिलाएँ आज आत्मनिर्भरता की सशक्त मिसाल बनकर उभर रही हैं। कभी सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने वाली महिलाएँ अब आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक रूप से मजबूत होकर अपने परिवार और समाज में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। इसके पीछे महतारी वंदन योजना, महतारी सदन और ई-रिक्शा वितरण जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का बड़ा योगदान है।जिले की दो लाख से अधिक महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 448 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस आर्थिक सहयोग से महिलाओं को न केवल आय का संबल मिला है, बल्कि उनके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई महिलाएँ स्वरोजगार से जुड़कर परिवार की आय बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी सदन एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। महिलाओं को सुरक्षित, सुविधायुक्त और संगठित मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साय सरकार ने जशपुर जिले में 18 महतारी सदन भवनों की स्वीकृति दी है। प्रत्येक भवन के लिए 29 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।कुल 5 करोड़ 22 लाख रुपये की लागत से बनने वाले ये भवन महिला स्व-सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण, बैठक, कौशल विकास और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनेंगे।

गेहूं फसल में कीट एवं खरपतवार से बचाव...कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी की समसामयिक सलाह

-संवाददाता-

सूरजपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। जिले के अधिकांश गांवों में गेहूं की बुवाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसी बीच कई क्षेत्रों से गेहूं की फसल में कीट, रोग एवं खरपतवार की समस्या सामने आ रही है, जिससे किसानों की मेहनत और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए समसामयिक तकनीकी सलाह जारी की है, ताकि समय रहते फसल को नुकसान से बचाया जा सके।

देरी से बोई फसल में दीमक का अधिक खतरा- कृषि विभाग के अनुसार देर से बोई गई फसलों में दीमक का प्रकोप अधिक देखा जाता है, जो जड़ों को नुकसान पहुंचाकर उत्पादन घटा सकती है। गेहूं की फसल में कीट नियंत्रण के लिए बीज उपचार को अत्यंत प्रभावी उपाय बताया गया है।

बीज उपचार के लिए अनुशंसित दवाइयाँ

- क्लोरोपाइरीफॉसः 0.9 ग्राम प्रति किलो बीज
- थायोमेथोक्साम 70 WS: 1 ग्राम प्रति किलो बीज
- फिप्रोनिल (रीजेंट 5 FS): 0.3 ग्राम प्रति किलो बीज बीज उपचार से दीमक सहित अन्य प्रारंभिक कीटों का प्रभाव

कम होता है और फसल की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित होती है।

कीट नियंत्रण के उपाय

- समय पर बोई गई फसल में यदि दीमक का आक्रमण दिखाई दे, तो सिंचाई करना लाभदायक होता है।
- गुलाबी तना छेदक कीट कम जुताई वाले खेतों में अधिक पाया जाता है। कीट दिखाई देते ही किनालफॉस (ईकालक्स) 800 मिली प्रति एकड़ का पत्तियों पर छिड़काव करें।

खरपतवार नियंत्रण की सलाह

संकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए

- क्लोडिनाफॉप 15 WP: 160 ग्राम प्रति एकड़
- पिनोक्साडेन 5 EC: 400 मिली प्रति एकड़

चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए

- 2,4-डी ईः 500 मिली प्रति एकड़
- मेटसल्फ्यूरॉन 20 WP: 8 ग्राम प्रति एकड़

संकरी व चौड़ी दोनों प्रकार की खरपतवार के लिए

- सल्फोसल्फ्यूरॉन 75 WG: 13.5 ग्राम प्रति एकड़
- सल्फोसल्फ्यूरॉन + मेटसल्फ्यूरॉन (BO WG): 16 ग्राम प्रति एकड़
- छिड़काव पहली सिंचाई से पहले या 10-15 दिन बाद करें।

वैकल्पिक विकल्प

- मेसोसल्फ्यूरॉन + आयोडोसल्फ्यूरॉन 3.6% WDG: 160 ग्राम प्रति एकड़

फैलेरिस माइनर (गुल्ली डंडा) नियंत्रण

बुवाई के 0-3 दिन बाद

- पाइरॉक्सासल्फोन 85 WG: 60 ग्राम प्रति एकड़,
- या पेंडिमेथालिन 30 EC: 2 लीटर प्रति एकड़

वैकल्पिक मिश्रण के रूप में

- एक्लोनिफेन 450 + डाइफ्लुफेनिकन 75 + पाइरॉक्सासल्फीनः 500-800 मिली प्रति एकड़

पहली सिंचाई के 10-15 दिन बाद

- क्लोडिनाफॉप + मेट्रिब्यूजिन (12+42% WP): 200 ग्राम प्रति एकड़

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

विविध इंजीनियरिंग कार्य हेतु ई–निविदा सूचना

क्रम सं. (1) : ई–निविदा संख्या : DRM-ENGG-BSP-T-170-25-26 दिनांकः 30/12/2025.
कार्य : बिलासपुर मंडल के वरिस्ठ मंडल अभियंता उत्तर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनूपपुर–कटनी सेक्शन में बड़े और छोटे पुलों में बैलास्ट रिटेनर, रिटेनिंग वॉल, विंग वॉल, टो वॉल, फ्लोरिंग, इंस्पेक्शन स्टेप्स, ट्रॉली रिफ्यूज, सेस चौड़ीकरण, ढलानों पर ड्राई पिचिंग और अन्य सुरक्षा कार्यों का अपग्रेडेशन और मजबूतीकरण।
निविदा मूल्य : ₹6,66,93,404/-। अमानत राशि : ₹4,83,500/- । कार्य पूर्णता की अवधि : 12 माह।

क्रम सं. (2) : ई–निविदा संख्या : DRM-ENGG-BSP-T-171-25-26 दिनांकः 30/12/2025.
कार्य : बिलासपुर मंडल के सहायक मंडल अभियंता/मनेन्द्रगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बड़े और छोटे पुलों में बैलास्ट रिटेनर, रिटेनिंग वॉल, विंग वॉल, टो वॉल, फ्लोरिंग, इंस्पेक्शन स्टेप्स, ट्रॉली रिफ्यूज, सेस चौड़ीकरण, ढलानों पर ड्राई पिचिंग और अन्य सुरक्षा कार्यों का अपग्रेडेशन और मजबूतीकरण।
निविदा मूल्य : ₹4,46,21,362/-। अमानत राशि : ₹3,73,100/- । कार्य पूर्णता की अवधि : 12 माह।

क्रम सं. (3) : ई–निविदा संख्या : DRM-ENGG-BSP-T-172-25-26 दिनांकः 30/12/2025.
कार्य : बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल अभियंता/उत्तर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यार्डों में आर सी सी नाले का निर्माण।
निविदा मूल्य : ₹2,86,82,181/-। अमानत राशि : ₹2,93,400/- । कार्य पूर्णता की अवधि : 12 माह।

निविदा जमा करने की आरंभ तिथि :– दिनांक **09.01.2026** से। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :–** दिनांक **23.01.2026 के 11:00** बजे तक।

उपरोक्त ई–निविदा सूचना की पूरी जानकारी https://www.ireps.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। उपरोक्त निविदाओं हेतु ई–टेन्डर के अलावा अन्य टेन्डर स्वीकार नहीं की जाएगी।

मंडल रेलवे प्रबंधक (अभियंता)
सीपीआर/10/578 द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर
South East Central Railway @secrail
RO.No.82584

न्यायालय नज़ूल अधिकारी,सूरजपुर
जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0/.../अ-20 (1) /2024-25

ईश्तहार

आगामी तिथि 16/1/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक केदारनाथ मित्तल आ0 स्व. विलायती राम, निवासी वार्ड नम्बर 6 भैयाथान रोड सूरजपुर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नगर सूरजपुर स्थित नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1863/4, 1864/2 रकबा क्रमषः 0.05, 0.01-1/2 डिसमिल भूमि का लीज अवधी 31.03.2026 को समाप्त होने से लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 16/01/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
सूरजपुर

जन्मदिवस की राजनीति और जनसेवा का सच

भव्य उत्सव बनाम गरीबों को कंबल वितरण,शिवपुर चरचा का असली जनसेवक कौन ?

-रवि सिंह-

कोरिया,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

राजनीति में जन्मदिवस अब निजी उत्सव नहीं रहे,वे शक्ति प्रदर्शन,भीड़ जुटाने और सोशल मीडिया की चमक का अवसर बन चुके हैं, बड़े-बड़े मंच,पोस्टर,केक,आतिशबाजी और जयकारों के बीच एक संदेश देने की कोशिश होती है देखिए,मेरे साथ कितने लोग हैं,लेकिन इसी शोरगुल के बीच शिवपुर चरचा में एक दूसरा दृश्य भी दिखा–जहाँ जन्मदिवस को गरीबों को कंबल वितरण जैसे शांत, मानवीय काम से जोड़ा गया,यही से असली सवाल जन्म लेता है जनता के लिए नेता कौन है? जो अपने जन्मदिवस पर जश्न मनवाए, या कोई दूसरा ऐसे ही या अन्य किसी विशेष दिवस के दिन किसी ठिठुरते गरीब को राहत दे?

सेवा दिखावे से बड़ी होती है : भव्य आयोजन क्षणिक होते हैं, मंच उतरते ही भीड़ छंट जाती है, पोस्टर उतर जाते हैं और उत्सव यादों में सिमट जाता है,लेकिन सर्द रात में ओढ़ा गया कंबल केवल कपड़ा नहीं होता–वह सम्मान, संवेदना और भरोसे का प्रतीक होता है, जनसेवा का असली मूल्य वहीं दिखाई देता है, जहाँ कोई कैमरा न हो, कोई नारा न हो–सिर्फ जरूरत और समाधान हो।

शिवपुर चरचा में तुलना स्वाभाविक है : जब एक ओर जन्मदिवस को शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनाया जाए और दूसरी ओर किसी विशेष दिन किसी के चेहरे पर राहत की मुस्कान लाई जाए,तो तुलना होना स्वाभाविक है,यह तुलना किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीति की प्राथमिकताओं के खिलाफ है। क्या जनसेवा का मतलब केवल साल में एक दिन दिखना है? या फिर हर दिन, हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़ा रहना?

नगर पालिका अध्यक्ष ने जन्मदिवस को बनाया नगर उत्सव का विषय : शिवपुर चरचा नगर पालिका में 1 जनवरी 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नजर नहीं आया,जिलेभर के भाजपा नेताओं का हुजूम शिवपुर चरचा में नजर आया,अवसर नगर पालिका के अध्यक्ष के जन्मदिवस का था और यह किसी उत्सव से कम नहीं आया।

जनता सब देखती है...

आज का मतदाता सिर्फ भाषण नहीं सुनता,वह व्यवहार देखता है। वह यह समझता है कि कौन अवसर को उत्सव बनाता है और कौन अवसर को सेवा में बदल देता है,शिवपुर चरचा की जनता के सामने यह सवाल अब खुलकर खड़ा है नेता वही जो जन्मदिन पर माला पहने,या वह जो उसी दिन किसी जरूरतमंद को कंबल ओढ़ाए? जन्मदिवस हर किसी का होता है,लेकिन उसे कैसे मनाया जाए, यही चरित्र बताता है, जनसेवा मंच से नहीं, मंशा से होती है, और अंततः इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो शोर नहीं,सहारा बनते हैं,तो सवाल आज भी वही है, शिवपुर चरचा का असली जनसेवक कौन?

ब्रांच मैनेजर की सराहनीय पहल

उत्कृष्ट सेवाओं से जीता ग्राहकों का दिल

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

बैंकिंग जगत में जहाँ अक्सर भीड़,देरी और औपचारिकताओं की शिकायतें सुनने को मिलती हैं,वहीं एक्सिस बैंक बैकुंठपुर शाखा ने सेवा-भाव और कार्यकुशलता की एक सकारात्मक मिसाल पेश की है। शाखा के ब्रांच मैनेजर संदीप चक्रबोरती और ऑपरेशन हेड सिंपल गुप्ता के नेतृत्व में ग्राहक अनुभव में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, हाल ही में शाखा में आए वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए न केवल बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल किया गया, बल्कि उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से सुनकर त्वरित समाधान भी दिया गया। इसी सेवा-उन्मुख कार्यशैली का परिणाम है कि शाखा ने इस तिमाही में ग्राहक संतुष्टि में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

मुख्य आकर्षण

- **डिजिटल साक्षरता पहल:** स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों के लिए डिजिटल बैंकिंग वर्कशॉप का आयोजन, ताकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सकें।
- **त्वरित ऋण सुविधा:** सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक देरी के ऋण उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका।
- **मिलनसार व्यवहार:** ग्राहकों का कहना है कि विनम्र और सुलभ रवैये के कारण वे अपनी समस्या सीधे प्रबंधन तक रख पाते हैं।

स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों ने इस समर्पण की खुले. तौर पर सराहना की है। वहीं,उच्च अधिकारियों ने भी शाखा के बेहतर प्रदर्शन और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण की प्रशंसा की है–जो बैंकिंग में भरोसे और मानवीय स्पर्श की अहमियत को रेखांकित करता है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक और अनुकरणीय पहल..

जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट से बनी पहली सड़क

-रवि सिंह-

एमसीबी,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक नई उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले की पहली सड़क का निर्माण प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग से किया गया है, यह सड़क पीडब्ल्यूडी रोड से मेंड्राडोल होते हुए भररीडांड तक लगभग 2.00 किलोमीटर लंबी है, जो ग्राम पंचायत परसगढ़ी क्षेत्र में स्थित है, यह पहल न केवल सड़क निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, बल्कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी और व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है।

कलेक्टर के मार्गदर्शन में पर्यावरण और विकास का संगम

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के दिशा-निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम के मार्गदर्शन में यह अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम पंचायत चनवारीडांड में स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई से प्राप्त प्लास्टिक को डामर के साथ मिश्रित कर सड़क निर्माण में उपयोग किया गया।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि यदि वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाए, तो अपशिष्ट भी एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है।

बेहतर गुणवत्ता,अधिक टिकाऊपन और कम लागत...

प्लास्टिक मिश्रित डामर से बनी यह सड़क सामान्य सड़कों की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ मानी जा रही है, सामान्य डामर सड़कः 4-5 वर्ष, प्लास्टिक मिश्रित सड़कः 6-7 वर्ष, तक टिकाऊ इसके साथ ही डामर की खपत कम होने से प्रति किलोमीटर लगभग 30,000 की बचत भी हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता मोतीराम सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिले की 5.49 किलोमीटर लंबी तीन सड़कों में प्लास्टिक मिश्रण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसके आधार पर भविष्य में अन्य सड़कों में भी इस तकनीक का विस्तार किया जाएगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट बना स्वच्छता और आजीविका का आधार...

जो प्लास्टिक कभी गंदगी और प्रदूषण का प्रतीक था,वही आज एक मजबूत और चमचमाती सड़क की नींव बन गया है,ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्र कर उसका पृथक्करण,सफाई और श्रेडिंग कर सड़क निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में स्वच्छाग्राहियों की अहम भूमिका है, जिन्हें इससे अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। खासकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से आर्थिक सशक्तिकरण को भी बल मिला है।

भविष्य के लिए मिसाल...

यह पहल न केवल वायु,जल और मृदा प्रदूषण को कम करने में सहायक है,बल्कि वैश्विक चुनौती बन चुके प्लास्टिक अपशिष्ट का स्थायी और व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है, एमसीबी जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण का यह प्रयोग आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और टिकाऊ विकास का मजबूत आधार बनने जा रहा है।

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई

82 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस

-संवाददाता-

एमसीबी,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने कड़ा रुख अपनाया है। योजना की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर 82 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी सतत निगरानी राज्य, जिला और जनपद स्तर पर की जा रही है, इसके बावजूद कुछ पंचायतों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखी।

लक्ष्य बनाम उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जिले को 15,314 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले अब तक 7,643 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जो समग्र रूप से जिले की उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं। योजना की समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं और समय-सीमा में निर्माण पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आवास मित्रों को प्रोत्साहन : निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवास मित्रों की भूमिका सशक्त की गई है। निरीक्षण कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के 92 आवास मित्रों को कुल 3.40 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यों में गति आई है।

नोटिस और चेतावनी...

इसके बावजूद 82 ग्राम पंचायतों में भौतिक प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई। बार-बार निर्देशों के बाद भी सुधार न होने पर संबंधित सचिवों को तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और तत्काल प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन ने दो टूक कहा है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य सतत जारी रहेगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ मिल सके।

आकड़े पर एक नजर...

- लक्ष्यः 15,314 आवास 7 पूर्णः 7,643
- कार्रवाईः 82 सचिवों को कारण बताओ नोटिस
- समय-सीमाः 3 दिन में जवाब
- चेतावनीः जवाब असंतोषजनक होने पर दंडात्मक कार्रवाई

प्रधानमंत्री की योजना से सूरजपुर को बड़ा लाभ...

57 मोबाइल मेडिकल यूनिट को दिखाई गई हरी झंडी,दूरस्थ इलाकों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा

-संवाददाता-

सूरजपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, 01 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य मंत्रीगण द्वारा 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस पहल से सूरजपुर जिले सहित प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा, सूरजपुर जैसे ग्रामीण और आदिवासी बहुल जिले में इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से प्राथमिक जांच, उपचार और आवश्यक दवाइयाँ अब सीधे गांवों तक उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को जिला मुख्यालय या बड़े अस्पतालों तक लंबी दूरी तय करने की मजबूरी नहीं रहेगी और समय पर इलाज संभव हो सकेगा।

जरूरतमंद क्षेत्रों पर विशेष फोकस : मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की लाइन-अप और तैनाती शासन स्तर पर की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूरजपुर जिले के सबसे जरूरतमंद और दुर्गम इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रभावी ढंग से पहुँचें।

स्थानीय प्रतिक्रिया : इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवम् दुबे ने कहा प्रधानमंत्री की यह योजना सूरजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिले के लिए संजीवनी साबित होगी। इससे गरीब और ग्रामीण परिवारों को समय पर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी।

जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता : यह पहल केंद्र और राज्य सरकार की जनस्वास्थ्य के प्रति गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आने वाले समय में इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन से सूरजपुर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है।

ओड़गी ब्लॉक के विशालपुर व नवाटोला में बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

-संवाददाता-

सूरजपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

ओड़गी ब्लॉक के ग्राम पंचायत विशालपुर के दो प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों–शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला विशालपुर और हाई सेकेंडरी स्कूल नवाटोला–में गुरुवार को बाल संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता पर केंद्रित व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, NICEF और एग्रिकोन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ, कार्यक्रम का नेतृत्व ओड़गी ब्लॉक के नवनियुक्त समन्वयक कृष्ण कुमार गुर्जर और धनराज जगते ने किया। दोनों विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण तथा छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई।

महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद : जागरूकता सत्रों में बच्चों और किशोरों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई,जिनमें–

- बाल विवाह की कुप्रथा
- लिंग आधारित एवं घरेलू हिंसा
- गुड टच-बैड टच की समझ
- शिक्षा का महत्व और बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य
- रूप से अधिक गुण की महत्ता

'पढ़ाई का कोना' जैसी पहलें शामिल रहीं। संवाद को सरल उदाहरणों और सहभागिता आधारित गतिविधियों से प्रभावी बनाया गया।

हेल्पलाइन की जानकारी और संकल्प- कार्यक्रम में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, आपातकालीन नंबर 112 और महिला हेल्पलाइन 181 की उपयोगिता और प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। समापन अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' के संकल्प की शपथ ली।

कबीर सिंह में शाहिद कपूर की जगह इस एक्टर को कास्ट करना चाहते थे संदीप रेड्डी वांगा

शाहिद कपूर ने साल 2023 में आई फिल्म कबीर सिंह में काम किया था। इस मूवी का निर्देशन संदीप वांगा रेड्डी ने किया था और शाहिद का किरदार मूवी में एक अल्फा मेल का था। मूवी ने उस समय अच्छा बिजनेस किया जबकि शाहिद की उस समय ज्यादा फिल्में सफल नहीं हो रही थीं। इस वजह से संदीप ने ये रोल पहले एक दूसरे एक्टर को ऑफर किया था।

दो साल पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से दर्शकों का दिल जीतने के दो साल बाद,रणवीर सिंह ने धुरंधर के साथ धमाकेदार वापसी की। उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन और लुक से सभी को चौंका दिया। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपने पहले कभी न देखे गए अवतार वाले रणवीर को जिसने भी देखा उनका मुरीद हो गया।

रणवीर सिंह ने ठुकरा दी थी फिल्म

धुरंधर की दीवानगी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है,ऐसे में लोग पुरानी चीजें भी ढूंढ़कर ला रहे हैं। ऐसे में संदीप रेड्डी वांगा का एक पुराना इंटरव्यू फिर से ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उन्होंने रणवीर को कबीर सिंह में लेने की बात कही थी। इस इंटरव्यू पर नेटिजन्स की चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस इंटरव्यू में निर्देशक ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म को ठुकरा दिया था। एक्टर ने क्या कहकर किया था मना?

रणवीर ने इसे डार्क मूवी कहकर ठुकरा दिया था। इसके बाद कबीर सिंह का रोल शाहिद कपूर के पास चला गया। कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म कबीर सिंह के बारे में बात की थी,जो उनकी तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी (2017) का रीमेक थी। फिल्म निर्माता ने बताया,मुझे रीमेक के लिए मुंबई से लगातार कॉल आ रहे थे। पहले तो यह ऑफर रणवीर सिंह को दिया गया था। मैं उनके साथ फिल्म करना चाहता था। लेकिन आखिरकार उन्होंने मना कर दिया,क्योंकि उस समय फिल्म उनके लिए बहुत डार्क थी।

शाहिद की फिल्में नहीं थी उतनी सफल

फिल्म में कियारा आडवाणी ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं शाहिद कपूर को ये रोल देने में संदीप श्योर नहीं थे। इस बारे में बात करते हुए शाहिद ने कहा, शाहिद के पिछले रिकॉर्ड को लेकर चिंता थी। उनकी किसी भी सोलो फिल्म ने तब तक 100 करोड़ रुपये नहीं कमाए थे,उनका सबसे ज्यादा कलेक्शन 65 करोड़ रुपये था। लोग कहते थे कि 55 करोड़ रुपये, 65 करोड़ रुपये तेलुगु फिल्मों का बिजनेस होता है। 'आप इस आदमी के साथ फिल्म क्यों कर रहे हैं? अगर रणवीर होते तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ज्यादा होता'। लेकिन मुझे शाहिद पर पूरा भरोसा था,वह एक शानदार अभिनेता हैं।

रिलीज से पहले लीक हुआ सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का सबसे जरूरी सीन?

सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर फैंस उत्साहित हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ,जिसमें सलमान को वर्दी में बर्फ में चीनी सैनिकों से लड़ते दिखाया गया। इसे फिल्म का लीक फुटेज माना जा रहा है।

सलमान खान इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर काम कर रहे हैं। फैंस के अंदर फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और वो लंबे समय से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे नेटिजन्स मान रहे हैं कि ये बैटल ऑफ गलवान की लीक फुटेज है।

वायरल वीडियो में सलमान खान वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ पर रेंगते हुए देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर खून और घाव के निशान हैं। फिर उन्हें उठते और बेसबॉल बैट उठाकर चीनी सैनिकों की पिटाई करते हुए

देखा जा सकता है।

यूजर्स ने ढूंढ़ ली सच्चाई

इस वीडियो को एक एक्स पर एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा,बैटल ऑफ गलवान का लीक फुटेज सलमान खान के कुछ सीन्स वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये रियल फुटेज नहीं है। कुछ यूजर्स ने कमेंट्स में इसकी सारी पोल पट्टी खोल दी।

इस वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया है। एक यूजर ने लिखा, जब यह घटना हुई, तब वहां बर्फ नहीं थी। लगता है यह एआई द्वारा बनाया गया है। दूसरे ने कहा, इंस्टाग्राम पर इसे एआई से बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यहां पर पढ़े लिखे लोग हैं।

क्या है बैटल ऑफ गलवान की कहानी?

अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित बैटल ऑफ गलवान भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई गलवान घाटी पर हुई झड़प को दिखाएगी। फिर से जीवंत करती है। एक दुर्लभ सीमा संघर्ष जो बिना किसी अस्त्र के इस्तेमाल के घातक रूप में बदल गया। इसके बजाय, सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई का सहारा लिया, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक बन गई।

कैमरे देखते ही उंगली दिखाने लगीं श्रद्धा कपूर

पिता के साथ अस्पताल के बाहर आई नजर, लोगों ने पूछा...सब ठीक है?

श्रद्धा कपूर की साल 2025 में एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन सोशल मीडिया पर अपने कथित रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती रहीं। हाल ही में श्रद्धा कपूर को एक अस्पताल के बाहर देखा गया है। श्रद्धा के साथ उनके पति शक्ति कपूर भी नजर आए हैं। यहां श्रद्धा ने जैसे ही पैपराजी के कैमरों को देखा तो गुस्से में उंगली दिखाने लगीं। अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें श्रद्धा पैपराजी को वीडियो और फोटो लेने से मना करती दिख रही हैं। एक वायरल वीडियो में, फूलों वाली शर्ट और ढीली पैंट पहने श्रद्धा अपने पिता शक्ति के साथ अस्पताल से बाहर निकलती हुई दिखाई दीं। श्रद्धा उन्हें सावधानीपूर्वक कार तक ले गईं और कार में बैठने में उनकी मदद की। कार में बैठते ही अभिनेत्री ने पैपराज़ी को देखा और उंगली से नहीं, नहीं का इशारा करते हुए उन्हें रिकॉर्डिंग न करने के लिए कहा। दोनों ने मास्क पहन रखा था। फिलहाल,दोनों के अस्पताल जाने का कारण अज्ञात है।

मौत से पहले लेडी सुपर स्टार की आखिरी फिल्म

मिला था नेशनल अवॉर्ड... 2 घंटे 26 मिनट की थ्रिलर मूवी कंपा देगी रूह...

अच्छी फिल्मों की फेहरिस्त में कई फिल्मों के नाम शुमार हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार की फिल्म रही और इस फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।

कौन सी है ये फिल्म,...

कहते हैं कि अच्छी फिल्में जब आती हैं तो सिनेमा के इतिहास में उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। अच्छी फिल्मों की फेहरिस्त में कई फिल्मों के नाम शुमार हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार की फिल्म रही है और इस फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।

कौन सी है ये फिल्म, चलिए आपको बताते हैं...

लेडी सुपरस्टार की फिल्म ने जीता था सबका दिल

साल 2017 में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम था मॉम । जी हां, वही फिल्म जिसमें श्रीदेवी नजर आई थीं। इस फिल्म में श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। फिल्म में श्रीदेवी की दमदार एक्टिंग की चर्चा के साथ साथ उनकी अपीयरेंस की भी खूब चर्चा रही। इस फिल्म में अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी जितनी शानदार थी उससे ज्यादा इसके किरदारों ने अपनी अलग छाप छोड़ी थी। फिल्म में श्रीदेवी ने देवकी सबरवाल का किरदार निभाया था,जो कि एक टीचर थीं।दरअसल फिल्म की कहानी श्रीदेवी और उनकी बेटी आर्या के इर्द-गिर्द घूमती है। आर्या का किरदार पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली ने निभाया। आर्या श्रीदेवी की सौतेली बेटी है और अपनी मां से प्यार नहीं करती लेकिन देवकी की जान आर्या में बसती है। जहां देवकी सबरवाल का किरदार निभाने वाली श्रीदेवी की बेटी के साथ 4 लोग दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म के बाद आरोपियों को सजा मिलती है। हालांकि इसके बाद सभी आरोपी बरी भी हो जाते हैं। ये देखकर देवकी को बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसकी बेटी का आरोपी इतनी आसानी से कैसे बच गए। फिर देवकी खुद ही इन चारों आरोपियों को सजा देने की ठान लेती है और एक एक करके इन सभी को ठिकाने लगाती है। इधर देवकी का साथ देने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हैं। फिल्म में दयाशंकर कपूर (डीके, जासूस) का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभाते हैं। उधर फिल्म में पुलिस ऑफिसर मैथ्यू फ्रांसिस के किरदार में अक्षय खन्ना दिखते हैं। क्लाईमैक्स में देवकी को अपनी बेटी मिल जाती है और वो आखिरी आरोपी को भी सजा दे देती है।

इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को नेशनल अवॉर्ड तक मिला था। वहीं ये फिल्म श्रीदेवी के करियर ये 300वीं फिल्म होती है और ये श्रीदेवी के करियर की भी आखिरी ही फिल्म होती है। जाते जाते श्रीदेवी वो जादू कर गईं जो हिंदी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। इस फिल्म को ओटीटी पर भी बहुत प्यार मिला है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और जी5 पर देख सकते हैं।

अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी पहली बार करेंगे इस फ्रेंचाइजी में साथ काम

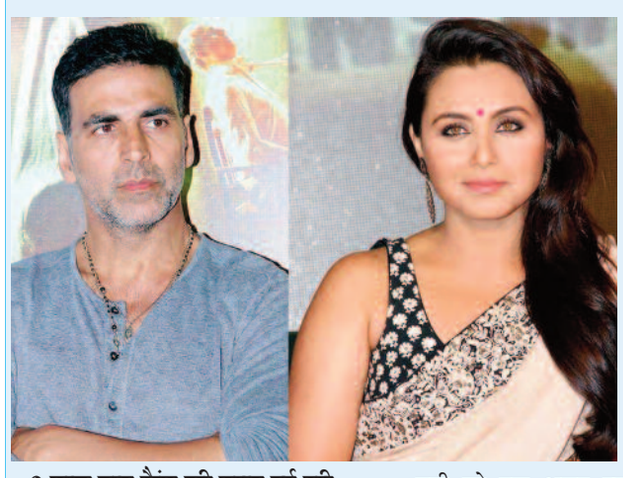

अगली कड़ी का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनके करीबी सूत्रों की मैं तो, ये पिछले कुछ सालों में किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ी कास्टिंग है। ओह माय गॉड अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा पसंद की गई फ्रेंचाइजी है। ओह माय गॉड के तीसरे पार्ट में रानी मुखर्जी का जुड़ना मूवी को एक अलग स्तर पर ले जाएगा। उनकी मौजूदगी फिल्म की कहानी में एक नई फ्रेशनेस लेकर आएगी।

8 साल बाद फैंस की मुराद हुई पूरी

अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी को बड़े पर्दे पर साथ देखने की तमन्ना फैंस की पूरी होने जा रही है। 90 के दशक के ये दोनों सुपरस्टार्स पहली बार अक्षय कुमार की एक सफल फ्रेंचाइजी में साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग मिड 2026 में शुरू हो जाएगी।

रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार दोनों ही 90 के दशक के मशहूर एक्टर्स हैं। इन दोनों ने अपने सफल करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी भी फैंस को दोनों को एक साथ पर्दे पर देखने का मौका नहीं मिला। अब सालों से दिल में दबी फैंस की ये तमन्ना पूरी होने जा रही है।रानी मुखर्जी अपने 28 साल के लंबे करियर में पहली बार खिलो ी कुमार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वह भी किसी नई फिल्म के लिए नहीं, बल्कि अक्षय कुमार की एक सफल फ्रेंचाइजी में रानी मुखर्जी की एंट्री हो रही है। किस प्रोजेक्ट के लिए रानी-अक्षय पहली बार आए हैं साथ

अक्षय की इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा होंगी रानी मुखर्जी

पिंकविला की एक खबर के मुताबिक, रानी मुखर्जी अक्षय कुमार की ओह माय गॉड की

कब शुरू होगी ओह माय गॉड 3 की शूटिंग?

इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ओह माय गॉड 3 का प्री-प्रोडक्शन वर्क शुरू हो चुका है और फिल्म 2026 मिड ईयर में फ्लोर पर जाएगी। फिल्म के निर्देशक अमित राय को मिल चुकी है,जो पहले के दो पार्ट्स के मुकाबले और भी बड़ी और कनेक्ट करने वाली है। अक्षय ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि ओह माय गॉड 3 के साथ कहानी से लेकर इमोशन, परफॉर्मेंस हर एक स्केल अप होने वाला है। रानी मुखर्जी का जुड़ना इस फ्रेंचाइजी को और भी बड़ा बना देगा।

ओह माय गॉड के पहले पार्ट में कांजीलाल की दुकान गिरने के बाद कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ता है। वहीं दूसरे पार्ट में महाकाल के भक्त कांति शरण मुद्गल (पंकज त्रिपाठी) के इर्द-गिर्द घूमती है,जिनके बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें बदनामी के कारण काफी कुछ झेलना पड़ता है। अब तीसरे पार्ट में कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।

खेल समाचार

टीम इंडिया 2026 में करेगी बांग्लादेश का दौरा

भारतीय क्रिकेट टीम इस साल बांग्लादेश का दौरा करने वाली है...इस बात की जानकारी खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ही दी है...

कई टी 20 और वनडे मैचों की सीरीज

नई दिल्ली,02 जनवरी 2026। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 के लिए अपने घरेलू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इस कैलेंडर में सबसे खास बात यह है कि भारत की टीम अगस्त-सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी। यह दौरा पहले स्थगित हो गया था जिसे अब फिर से तय किया गया है। भारत तीन वनडे और तीन टी20 मैच खेलेगा।

बांग्लादेश जाएगी भारतीय टीम

भारतीय टीम 28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचेगी। वनडे सीरीज 1, 3 और 6 सितंबर को होगी, जबकि टी20 सीरीज 9, 12 और 13 सितंबर को खेली जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम अपने देश लौट जाएगी।

बीसीबी के क्रिकेट संचालन प्रभारी शाहरियार नाफीस ने क्रिकबज को बताया, बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीरीज पहले स्थगित हो गई थी उसे फिर से तय कर दिया गया है। भारत का यह दौरा बांग्लादेश के 2026 के घरेलू सीजन का हिस्सा है। इस सीजन में बांग्लादेश पाकिस्तान, न्यूजीलैंड,ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज जैसी टीमों के खिलाफ भी सभी फॉर्मेट में द्विपक्षीय सीरीज खेलेगा।

टी 20 वर्ल्ड कप के बाद सीजन शुरू

बांग्लादेश का घरेलू सीजन मार्च में पुरुष टी20 विश्व कप के बाद शुरू होगा। मार्च में पाकिस्तान की टीम तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। यह सीरीज 12 से 16 मार्च तक खेली जाएगी। इसके बाद मई में पाकिस्तान दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए फिर से आएगा। ये टेस्ट मैच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे और 8-12 मई और 16-20 मई को खेले जाएंगे।

न्यूजीलैंड की टीम भी करेगी दौरा

अप्रैल-मई में न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। यह एक पूरी तरह से सफेद गेंद की सीरीज होगी। इसमें तीन वनडे मैच 17 अप्रैल से शुरू होंगे, जिसके बाद 27 अप्रैल से 2 मई तक तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। जून में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इसी तरह की सफेद गेंद की सीरीज के लिए आएगी। इसमें तीन वनडे मैच 5 जून से शुरू होंगे, और तीन टी20 मैच 15 से 20 जून के बीच खेले जाएंगे। भारत का यह दोबारा तय किया गया दौरा सीजन के बाद में होगा। इसके बाद बांग्लादेश अपना घरेलू कैलेंडर अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ समाप्त करेगा। यह सीरीज भी डब्ल्यूटीसी का हिस्सा होगी। टेस्ट मैचों से पहले 22-24 अक्टूबर तक एक तीन दिवसीय वार्म-अप मैच खेला जाएगा। टेस्ट मैच 28 अक्टूबर-1 नवंबर और 5-9 नवंबर को होंगे।

असम के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज

भारत आएगी नामीबिया की महिला क्रिकेट टीम

गुवाहाटी,02 जनवरी 2026। नामीबिया की महिला क्रिकेट टीम 8 जनवरी से असम के खिलाफ चार मुकाबले खेलेगी। यह टूर असम क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट नामीबिया के बीच एक आपसी समझौते का हिस्सा है। टूर के दौरान,नामीबिया की टीम दो 50-ओवरों के मैच और दो टी20 मुकाबले खेलेगी। यह मुकाबले 8-11 जनवरी तक एमएसए स्टेडियम, मंगलदाई और एसीए क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, फुलुंग,नॉर्थ गुवाहाटी में खेले जाने हैं। एसीए सेक्रेटरी सनातन दास ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, यह सीरीज असम क्रिकेट के लिए एक अहम पड़ाव है, जो भारत और नामीबिया के बीच खेल के रिश्तों को मजबूत करेगी। दोनों टीमों की खिलाड़ियों को अपने कौशल,प्रतिस्पर्धा और खेल की सच्ची भावना दिखाने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन्होंने कहा, असम क्रिकेट एसोसिएशन इस रोमांचक सीरीज की मेजबानी करने और असम क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट नामीबिया के बीच लंबे समय तक चलने वाले खेल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। एसीए के तय कार्यक्रम के अनुसार, नामीबिया की सीनियर महिला टीम 6 जनवरी को गुवाहाटी पहुंचेगी। मुकाबलों की शुरुआत से पहले 7 जनवरी को प्रैक्टिस सेशन होगा। दोनों टीमों के बीच शुरुआती 50 ओवरों का मैच 8 जनवरी को खेला जाएगा। इसके बाद अगले दिन उसी वेन्यू पर दूसरे वनडे मैच का आयोजन होगा। दोनों टी20 मैच 10 और 11 जनवरी को खेले जाने हैं। इसके बाद नामीबिया की टीम 12 जनवरी को अपने वतन वापस लौटेगी।

टी 20वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीकी टीम घोषित,मफाका-स्मिथ को मौका

जोहान्सबर्ग,02 जनवरी 2026। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है, जिसकी कमान एडेन मार्करम को सौंपी गई है। उनके साथ युवा तेज गेंदबाज क्वेना मफाका और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज जेसन स्मिथ को शामिल किया गया है। हालांकि, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम में जगह नहीं बना सके हैं। स्मिथ का चयन उनकी हालिया शानदार फॉर्म के कारण हुआ है। स्मिथ ने 2024 में अपना टी20 डेब्यू किया था और उनका स्ट्राइक रेट 128.30 है। वह फिलहाल एसए 20 में एमआई केपटाउन के लिए खेल रहे हैं। स्मिथ और मफाका के अलावा,कॉर्बिन बॉश,देवाल्ड ब्रेविस,टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा और जॉर्ज लिंडे को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया गया है।

हेड कोच शुक्री कॉनराड ने कहा, हम उपमहाद्वीप में लौट रहे हैं, जहां हमने हाल ही में मेजबान भारत के खिलाफ खेला था। उन परिस्थितियों में खेलने से हमें जो अनुभव मिला है, वह निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में हमारे लिए फायदेमंद होगा। वर्ल्ड कप टीम के लिए चुने गए कई खिलाड़ी उस दौरे पर थे और उन्होंने उन पिचों का अनुभव किया है जिनका सामना हमें शायद करना पड़ेगा। जब हम भारत पहुंचेंगे तो यह उनके लिए बहुत काम आएगा। वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने से पहले हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए इस महीने के अंत में टीम का ऐलान किया जाएगा।

कगिसो रबाडा पसली की चोट के कारण भारत के खिलाफ हालिया व्हाइट बॉल दौरे से बाहर रहे थे, जिसके बाद उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। साउथ अफ्रीका की इस टीम में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्त्जे का नाम भी शामिल है,जो टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज थे। भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। इसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाना है। साउथ अफ्रीकी टीम को ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ रखा गया है। यह टीम 9 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

जब अस्पताल अमीरों के मॉल बन जाएँ और गरीबों के लिए कब्र

एक ही मशीन...एक ही जांच...फिर दरों में जमीन-आसमान क्यों?

■ आयुष्मान के भरोसे बीमार,बिल देखकर बेहोश...इलाज के नाम पर लूट और सरकार की चुप्पी...

■ स्वास्थ्य टूरिज्म के नीचे दबती आम आदमी की सांस...इलाज एक, रेट अनेकः छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा या खुली लूट?

न्यूज डेस्क

रायपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ में आज बीमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है, सबसे बड़ा संकट है इलाज की कीमत,बीमारी शरीर तोड़ती है,लेकिन इलाज आदमी की पूरी जिंदगी तोड़ देता है,सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत जिसे गरीब की ढाल कहा गया निजी अस्पतालों में पहुँचते ही 'चिल्लर योजना' बन जाती है,कागज पर पाँच लाख का भरोसा, हकीकत में, जांच के नाम पर हजारों,सर्जरी के नाम पर लाखों की मांग, इमारत बड़ी,तो इलाज महंगा,यह कौन सा मेडिकल साइंस है? छत्तीसगढ़ में आज बीमारी से ज़्यादा खतरनाक हो गया है इलाज का खर्च,राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है,जहाँ सरकारी अस्पताल संसाधनों के बावजूद भरोसा नहीं जगा पा रहे और निजी अस्पताल इलाज के नाम पर खुली आर्थिक मनमानी कर रहे हैं,सवाल सीधा है क्या स्वास्थ्य अब सेवा नहीं,सिर्फ़ मुनाफ़े का धंधा बन चुका है? छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत,निजी अस्पतालों के शुल्क संरचना में भारी अंतर और गरीब-मध्यम वर्ग के लिए इलाज की पहुंच को लेकर सवाल तेजी से उठ रहे हैं, मरीजों का कहना है कि बड़ी बिल्डिंग,आधुनिक मशीनें और निजी चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर जांच,इलाज और सर्जरी के शुल्क का निर्धारण असमान और मनमाना है,जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना ने लाखों लोगों को इलाज की राहत दी है, लेकिन निजी अस्पतालों में शुल्क समान नहीं होने और महंगी सेवाओं के कारण गरीब मरीज आर्थिक बोझ में फँसते हैं,समान दर नीति,उचित निगरानी और किफायती इलाज से ही स्वास्थ्य सेवाएँ सभी के लिए बेहतर और न्यायपूर्ण बन सकती हैं,अगर सरकार सभी अस्पतालों के लिए मानकीकृत दर तय करेगी और भुगतान प्रणाली को सरल बनाएगी,तो छत्तीसगढ़ एक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मिसाल बन सकता है और जनता को वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

एक ही जांच,अलग-अलग दामः यह कैसा न्याय?

सोनोग्राफी,ईसीजी,एक्स-रे,सीटी-स्कैन–इन सभी जांचों में लगने वाली मशीनें,तकनीक, बिजली, स्टाफ और मेंटेनेंस की लागत लगभग हर अस्पताल में समान होती है,फिर ऐसा कैसे है कि एक अस्पताल में सोनोग्राफी 300-500 रुपये में,और दूसरे में वही जांच 2500-3000 रुपये में? क्या रेट तय करने का पैमाना मरीज नहीं,बिल्डिंग की भव्यता है? क्या काँच की दीवारें,एसी रिसेप्शन और बड़े होर्डिंग इलाज को महँगा कर देते हैं? अगर हाँ, तो यह स्वास्थ्य नहीं,ब्रांड-बिक्री है।

सरकारी अस्पताल... मशीनें हैं,पर व्यवस्था नहीं...

राज्य के शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर हैं,मशीनें हैं, बजट है,लेकिन फिर भी आम आदमी निजी अस्पताल जाने को मजबूर है, कारण साफ़ हैः समय पर जांच नहीं, ऑपरेशन में अनावश्यक देरी, अव्यवस्थित सिस्टम और जवाबदेही का अभाव, अगर सरकार सच में चाहती है कि गरीब और मध्यम वर्ग निजी अस्पतालों की लूट से बचे, तो सरकारी अस्पतालों में निजी जैसी सुविधा और अनुशासन लागू करना ही होगा,सिर्फ इमारत बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होती,प्रबंधन और इच्छाशक्ति से होती है।

आयुष्मान काग़ज़ों में करोड़ों का, निजी अस्पतालों में 'चिल्लर'

बीमारी नहीं मार रही,इलाज की कीमत जान ले रही है...मार्बल की इमारतें,कर्ज में डूबी जिंदगियाँ

स्वास्थ्य सेवा या सिंडिकेट राज? छत्तीसगढ़ में इलाज बना व्यापार

इलाज नहीं,लूट चल रही है-छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कड़ा सवाल

इलाज या लूट ?...आयुष्मान के नाम पर निजी अस्पतालों का खुला कारोबार

निजी अस्पतालों की मनमानीः सरकार क्यों मौन है?

सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य तय हो सकते हैं, जब पेट्रोल-डीजल,राशन, परिवहन–सब पर सरकारी नियंत्रण हो सकता है, तो फिर जांच,ऑपरेशन,आईसीयू और बेड चार्ज पर कोई मानक दर क्यों नहीं? क्या सरकार नहीं चाहती,या फिर यह क्षेत्र किसी ऐसे बड़े सिंडिकेट के हवाले है,जहाँ से मोटा मुनाफ़ा निकलता है–और मरीज सिर्फ़ शिकार बनता है?

एक राज्य-एक दर क्यों नहीं?

छत्तीसगढ़ सरकार को तुरंत यह तय करना चाहिए किः सभी निजी अस्पतालों के लिए जांच और ऑपरेशन की मानक दरें लागू हों,हर अस्पताल में रेट लिस्ट सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए,तय दर से अधिक वसूली पर कठोर दंड और लाइसेंस कार्रवाई हो,गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज को सुलभ और समान बनाया जाए स्वास्थ्य कोई लग्जरी नहीं,मौलिक अधिकार है,बीमारी किसी की आर्थिक हैसियत देखकर नहीं आती, तो इलाज का दाम भी हैसियत देखकर तय नहीं होना चाहिए।

आखिरी सवाल-सरकार से जवाब चाहिए...

क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस लूट पर लगाम लगाएगी? या फिर आंख मूंदकर देखती रहेगी–जहाँ मुनाफ़ा कुछ लोगों के हाथ में और कर्ज,बेबसी और मौत आम आदमी के हिस्से में आती है? अब वक्त बयानबाजी का नहीं, नीति और कार्रवाई का है, अगर आज दरें तय नहीं हुईं,तो कल इलाज सिर्फ़ अमीरों का अधिकार बन जाएगा और गरीब के लिए अस्पताल नहीं, सिर्फ़ प्रतीक्षा और पीड़ा बचेगी।

आयुष्मान निजी अस्पतालों में क्यों बन जाती है चिल्लर?

इलाज एक,मशीन एक... फिर रेट में आसमान-जमीन का फर्क क्यों? सरकार की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत आज जमीन पर आते-आते निजी अस्पतालों में बेअसर काग़ज बनकर रह जाती है, योजना का उद्देश्य साफ था गरीब से अमीर तक,हर नागरिक को बिना आर्थिक बोझ के इलाज,लेकिन हकीकत यह है कि निजी अस्पतालों की चौखट पर कदम रखते ही आयुष्मान की ताकत खत्म हो जाती है।

बिल्डिंग देखकर इलाज की कीमत क्यों?

जांच वही,मशीन वही,सर्जरी वही,डॉक्टर वही फिर सिर्फ इसलिए कि अस्पताल की इमारत बड़ी और चमकदार है,सीटी स्कैन, सोनोग्राफी,ईसीजी और सर्जरी के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं,क्या इलाज की कीमत सेवा से तय होनी चाहिए या इमारत से?

दर तय नहीं...तो लूट तय...

निजी अस्पतालों में जांच के दर्जनों नाम,हर नाम के अलग-अलग भारी रेट,सर्जरी के पैकेज ऐसे कि मध्यम वर्ग भी कांप जाए,नतीजा यह कि जमीन बिकती है,गहने गिरवी पड़ते हैं,कर्ज का पहाड़ खड़ा हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब मरीज बेबसी में कहता है..हे भगवान,इससे अच्छा तो उठा ही ले।' यह सिर्फ बीमारी की पीड़ा नहीं,यह महंगे इलाज की मानसिक यातना है।

सरकार के पास अधिकार है,फिर डर क्यों?

जब दवाओं के दाम तय हो सकते हैं,पेट्रोल-डीजल के रेट नियंत्रित हो सकते हैं,अनाज की कीमत पर नीति बन सकती है तो फिर जांच,सर्जरी और इलाज की दर क्यों नहीं? आयुष्मान में जो दर तय है, वही दर सभी निजी अस्पतालों पर अनिवार्य क्यों नहीं? क्या सरकार पीछे इसलिए हटती है क्योंकि बड़े अस्पतालों का दबाव है? कोई स्वास्थ्य-सिंडिकेट नीतियां तय कर रहा है? मुनाफा, सेवा से ऊपर रखा गया है?

स्वास्थ्य टूरिज्म या स्वास्थ्य व्यापार?

छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की इमारतें तेजी से बढ़ रही हैं,मल्टी-स्पेशलिटी नाम के बोर्ड लग रहे हैं लेकिन सवाल यह है क्या इन इमारतों के साथ सेवा-भाव भी बढ़ रहा है,या सिर्फ इलाज को व्यापार बनाया जा रहा है? महंगी इमारतें कहीं न कहीं आम आदमी को इलाज से दूर और निराशा व इच्छा-मृत्यु की सोच तक धकेल रही हैं।

अब फैसले टालने का समय नहीं...

आज जरूरत है निजी और सरकारी अस्पतालों में एक समान दर प्रणाली,आयुष्मान दर को सभी अस्पतालों पर अनिवार्य करने की बिल्डिंग नहीं, इलाज को केंद्र में रखने की,अगर आज सरकार और स्वास्थ्य मंत्री ने ठोस निर्णय नहीं लिए,तो आने वाला कल यह कहेगा– बीमारी से कम लोग मरे,इलाज की कीमत से ज़्यादा,अब सवाल सिर्फ नीति का नहीं,नियत और नीयत दोनों का है।

आयुष्मान भारत योजनाः आंकड़े और छत्तीसगढ़ की स्थिति

योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लक्ष्य है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज हर साल प्रदान करना, छत्तीसगढ़ में योजना की प्रगति अब तक 78 लाख से अधिक लाभार्थियों ने निःशुल्क इलाज का लाभ उठाया है राष्ट्रीय स्तर पर भी अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है,राज्य में लगभग प्रतिदिन 1,600-1,700 दावे प्रस्तुत हो रहे हैं, जिनका कुल भुगतान लगभग 4 करोड़ प्रतिदिन तक जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार को केंद्र से अब तक कुल 505 करोड़ राशि प्राप्त हुई है,जिससे दावों का भुगतान जारी रखा जा रहा है, पर समस्या आज भी बनी हुई हैः कई निजी अस्पताल आयुष्मान भुगतान में देरी और कम दरों को लेकर असंतुष्ट हैं,जिससे इलाज के शुल्क और सेवाओं पर विवाद कायम है।

निजी बनाम सरकारी अस्पताल...दरों में अंतर क्यों?

आज तक कोई समान दर नहीं भारत में आयुष्मान भारत के तहत लगभग 30,985 अस्पताल पैनल में शामिल हैं, जिनमें से लगभग 13,883 (45%) निजी अस्पताल हैं, हालांकि इनकी संख्या सरकारी अस्पतालों के मुकाबले कम है, वे कुल इलाजों का करीब 52% हिस्सा प्रदान कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि इलाज की भारी मांग निजी सेक्टर में भी है, लेकिन दरें तय करने की कवायद पारदर्शी या समान नहीं है।

खर्च का असमान अनुभव

एक ही जांच या ऑपरेशन का शुल्क बड़े शहर के निजी अस्पताल में अलग और छोटे ग्रामीण क्लिनिक में अलग होता है,इस तरह का भेदभाव दवाओं,जांच और सर्जरी के खर्चों में गरीब पर भारी बोझ डालता है,स्वास्थ्य प्रणाली में निजी अस्पताल बुनियादी ढांचे,बिल्डिंग आकार,उपकरणों की कीमत और स्थानीय बाजार के अनुसार शुल्क तय करते हैं,जिससे असमानता और बढ़ जाती है।

समस्याएँ और उनकी वजहें...

शुल्क नियंत्रण का अभाव भारत में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अभी तक एक समान दरों की सार्वभौमिक नीति लागू नहीं की गई है, जिससे निजी अस्पताल स्वयं दर तय करते हैं गरीब मरीजों को इलाज से पूर्व आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, कुछ राज्यों जैसे राजस्थान ने 'Right to Health Care Act' के तहत मुफ्त OPD/IPD की बात की है, लेकिन हर राज्य में लागू नहीं है।

आम जनता और विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

मरीजों की आवाज-

- निजी अस्पतालों में महंगे शुल्क के कारण कई गरीब मरीज इलाज से बचते हैं।
- सर्जरी/विस्तृत जांच के लिए फीस अलग-अलग होने के कारण लोग आर्थिक तंगी में धराशाई हो जाते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का विचार-

- निजी अस्पतालों में दरों का भेदभाव सामाजिक न्याय के विपरीत है।
- सरकार को समान दर निर्धारण, पारदर्शिता और निगरानी की आवश्यकता है।

सरकार और नीति में क्या बदलाव की जरूरत?

समान दर निर्धारण छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र को यह देखना होगा किः

- निजी अस्पतालों में जांच,इलाज एवं सर्जरी पर बिल्डिंग/इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर दरें भिन्न न हों
- गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए किफायती दर सुनिश्चित हों

आयुष्मान योजना के कार्यान्वयन में सुधार

- भुगतान प्रक्रिया को तेज करना और अस्पतालों को समय पर राशि उपलब्ध कराना
- धोखाधड़ी रोकने के लिए निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग

कुछ महत्वपूर्ण सवाल...

- सरकार के पास अधिकार है, फिर निजी अस्पताल बेलगाम क्यों?
- आयुष्मान दर सभी पर लागू क्यों नहीं? किसका दबाव भारी?
- क्या छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य नीति जनता के लिए है या निवेशकों के लिए?
- रेट तय नहीं, इसलिए लूट तय–कब जागेगा स्वास्थ्य विभाग?

क्या सरकार ऐसा कर सकती है...

- समान दर, समान इलाजः क्या छत्तीसगढ़ बना पाएगा स्वास्थ्य की मिसाल?
- आयुष्मान बनाम हकीकतः छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच
- बिल्डिंग बड़ी,बिल बड़ा–इलाज का यह कैसा गणित?

तमनार हिंसा...महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी,अर्धनग्न किया

खेत में गिराकर घसीटा,रो-रोकर बोली...भाई छोड़ दो,लोगों ने बताया साजिश

रायगढ़,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने उसे आधा किमी तक दौड़ाया। जब वह खेत में गिर गई, तो वर्दी फाड़-फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का प्रदर्शनकारियों ने वीडियो भी बनाया,जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 40 सेकेंड के इस वीडियो में महिला

आरक्षक रो-रोकर प्रदर्शनकारियों को भाई बोलकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि,क्या करने आई थी। चप्पल से मारूं अभी। चलो भाग जाओ यहां से। उसके बाद उसे छोड़कर लोग चले जाते हैं। इससे पहले महिला आईटी को लात मारने का वीडियो सामने आया था। यह हिंसक झड़प 27 दिसंबर 2025 को हुई थी। वहीं 14 गांवों के लोगों ने प्रेस नोट जारी कर घटना का विरोध किया है। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की माने तो शांतिपूर्ण चल रहे जनआंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई है। वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन के प्रति जनता का बढ़ता अविश्वास और आक्रोश बताया है।

शराब घोटाला...भूपेश के बेटे चैतन्य को हाईकोर्ट से मिली जमानत

ईडी-ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती...5 महीनों से जेल में हैं बंद

बिलासपुर,02 जनवरी 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने आज शुक्रवार को चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर आदेश जारी कर दिया है। शराब घोटाला केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। यह राहत उन्हें प्रवर्तन निदेशालय और छत्तीसगढ़ एंटी-करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज केसों में मिली है। ईडी ने चैतन्य को पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जबकि

भ्रष्टाचार के मामले में सितंबर में एसीबी ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब वे पहले से ही जेल में थे। जांच एजेंसियों के अनुसार यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के संरक्षक थे और उन्होंने करीब 1,000 करोड़ रुपए का लेन-देन व्यक्तिगत रूप से संभाला। इसके अलावा एसीबी का दावा है कि चैतन्य बघेल को हिस्से के तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपए मिले और इस पूरे घोटाले की कुल रकम 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। वहीं बेटे को जमानत मिलने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं हो सकता।

चैतन्य बघेल तक कैसे पहुंची ईडी : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील सौरभ पाण्डेय ने बताया था कि शराब घोटाले का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें चैतन्य बघेल ने बहुत सारे पैसे को लेयरिंग की है। 1000 करोड़ का लेनदेन किया है। पप्पू बंसल ने अपने बयान में खुलासा किया है।

शराब के घोटालों के पैसों को चैनलाइज्ड करके चैतन्य बघेल तक पहुंचाया जाता था। लिकर स्कैम का पैसा अनवर ढेबर के जरिए दीपेंद्र चावड़ा फिर वह पैसा केके श्रीवास्तव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल औ उसके बाद चैतन्य बघेल के पास यह पैसा पहुंचता था। सौरभ पाण्डेय ने बताया था कि शराब घोटाले में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों के आपस में कनेक्शन है। अनवर ढेबर से मोबाइल चैट और रिकॉर्डिंग मिली है। चैतन्य बघेल तक पैसा पहुंचाया गया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)